

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल सिंगरौली के बैढ़न परिक्षेत्र के वन कक्ष PF-261 के रकबा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अन्तर्गत कोयला खनन व्यपवर्तन का मेसर्स एन.सी. एल. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/149270/2021/

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्र. 6-MPC 059/2013-BHO/279, दिनांक 28.02.2024

विषयांकित परियोजना के संबंध में आपने संदर्भित पत्र दिनांक 28.02.2024 से 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई 19 बिन्दुओं की जानकारी में से 02 बिन्दु की जानकारी वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक 4511 दिनांक 16.07.2024 से एवं 17 बिन्दु की जानकारी मेसर्स नॉर्डन कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 09.07.2024 से प्रस्तुत की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार की 19 बिन्दुओं की बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

1. The State Govt. has mentioned that the proposal is for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project and as per records available on Parivesh portal it has been found that the Ministry vide letter No 8-85/2005-FC dated 14.09.2010 has approved diversion of 180 ha forest land for Khadia Project of Northern Coalfields Limited (NCL) in Sidhi District. Therefore the compliance of conditions stipulated in said approval needs submission.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र No 8-85/2005-FC dated 14.09.2010 से प्रदत्त सशर्त अनुमति में अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है जो Annexure-A पर संलग्न है।

2. Present status of Compensatory Afforestation (CA) which was then approved in case of 180 ha diverted forest land needs submission along with the KML files.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी, सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/4517 दिनांक 16.07.2024 से प्रतिवेदित किया गया है कि प्रभावित रकबा 180.00 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में सिंगरौली वन मंडल के दूगने वनक्षेत्र रकबा 360.00 हेक्टेयर वनभूमि में वर्ष 2013-14 में क्षेत्र तैयारी का कार्य एवं वर्ष 2014-15 में वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। उक्त वृक्षारोपण परियोजना की अवधि 10 वर्षीय थी जो कि वर्ष 2022-23 में पूर्ण हो चुकी है। पौधों की वृद्धि एवं जीवितता कैम्पा के नियमानुसार है। प्रति तथा वृक्षारोपण की KML files संलग्न प्रस्तुत है।

3. Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 31.03.2024 तक रकबा 208.89 हेक्टेयर क्षेत्र में ओवर बर्डन डम्प एवं रकबा 156.5 हेक्टेयर मैदानी क्षेत्र अर्थात् कुल रकबा 365.39 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जैविक समतलीकरण कार्य अनुमोदित खनन एवं खदान बन्द करने की योजना के अनुरूप है।

20 मिलियन टन प्रति वर्ष कोयला उत्पादन हेतु स्वीकृत माईनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान के अनुसार दिनांक 31.03.2024 तक कुल रकबा 365.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाना था एवं रकबा 365.39 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया जा चुका है।

4. Cost Benefit analysis indicating the CB ratio of 1:121.306 has been submitted which appears to be exorbitantly high. The same needs to be revisited and estimated using appropriate techno-economic tools for estimation of all parameters and their discounting to arrive at same values of cost and future benefits as per prescribed format.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा संशोधित कास्ट बेनिफिट एनालिसेस पत्रक ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर संलग्न प्रस्तुत किया गया है जो Annexure-B पर संलग्न है।

5. The State Govt. reported that the proposed forest land for diversion is located within 1 Km from the Wildlife Sanctuary/ National park/ Biosphere Reserve/ Tiger Reserve/ Elephant corridor. However, specific details have not been submitted. Therefore, the comments of the CWLW in this regard and status of wildlife clearance needs submission.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि आपको प्रस्ताव भेजते समय इस भू-प्रबंध कार्यालय के पत्र दिनांक 31.01.2024 में "संरक्षित क्षेत्र 01 कि.मी. की परिधि में आता है" लेख हो जाना टंकन त्रुटि है इसके स्थान पर प्रस्तावित वनक्षेत्र किसी निकटतम संरक्षित क्षेत्र के 01 किलो मीटर के परिधि में नहीं आता है पढ़ा जावे।

वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा प्रस्ताव के भाग-2 में संरक्षित क्षेत्र 01 किलो मीटर की परिधि में नहीं आता है लेख किया गया है तथा अपने स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में भी इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित रकबा 53.142 हे. वनभूमि न तो संरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है और न ही किसी संरक्षित क्षेत्र के 10 किलो मीटर के भीतर है। अतः मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) के अभिमत की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. The State Govt. shall clarify whether the present proposal requires Wildlife Management plan or otherwise.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में लेख है कि उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा सिंगरौली वन मंडल अन्तर्गत एक अन्य दुधीचुआ परियोजना रकबा 443.00 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल द्वारा तैयार की वन्यप्राणी प्रबंधन योजना तैयार की गई एवं इसके सुझाव के अनुसार राशि रुपये 21.34 करोड़ कैम्पा मद में जमा किये जा चुके हैं जिसका UTR No. SBINR 52020122303364518 दिनांक 23.12.2020 है।

7. Details of coal evacuation plan and involvement/requirement of additional forest land, if any, shall be intimated.

इस बिन्दु के सम्बन्ध उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष क्षमता के लिए अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खड़िया खुली परियोजना की कोयला प्रेषण इस प्रकार होगी:-

खड़िया विस्तार परियोजना द्वारा 20 मिलियन टन द्वारा उत्पादित कोयले की 20 MTPA की आपूर्ति मौजूदा CHP (कोल हैण्डलिंग प्लांट) की 10.0 MTPA क्षमता और एक आगामी 4 MTPA CHP के माध्यम से की जाएगी। शेष कोयला मौजूदा कृष्णाशिला CHP, Wharfwall और प्रस्तावित Western stream of CHP के माध्यम से प्रबंधित किया जाएगा। उपरोक्त कोयले का एक हिस्सा कोयला सड़क मार्ग द्वारा भेजा जा सकता है, जैसा कि सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार होगा।

कोयला निकासी के उद्देश्य के लिये खड़िया विस्तार खुली खदान परियोजना को किसी अतिरिक्त वनभूमि की आवश्यकता नहीं है।

8. Satellite imagery shows that safety zone in the Khadia and the adjoining mine has not been maintained. The State Govt. shall submit the justification along with the status of safety zone maintained in the mined out area.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :-

1. खड़िया खुली खदान परियोजना के साथ लगी हुई खदानें दुधीचुआ ओसीपी और कृष्णशिला ओसीपी हैं, जो कि नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के अन्तर्गत ही आती हैं।
 2. सिंगरौली कोलफील्ड्स की कोयला परतें, जैसे कि पुरेवा टॉप, पुरेवा बॉटम और तुर्रा लगातार हैं। खड़िया खुली खदान परियोजना और इसके आस-पास की खदानें, जैसे कि कृष्णशिला ओसीपी और दुधीचुआ ओसीपी, समान लगातार परतों पर संचालित हो रही हैं साथ ही पड़ोसी खदानें बैरियर पर Sequential Operation में कोयला निकालती हैं ताकि अधिकतम कोयला निकाला जा सके। वर्तमान में पौधारोपण माइन बैरियर पर स्थित लगभग 36 मिलियन टन कोयला निकासी को निष्फल कर देगा, जो संसाधन के सर्वोत्तम उपयोग के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा।
 3. इसके अलावा जो कोयला बचा रहेगा, वह स्वतः ही आग पकड़ सकता है, जिससे पर्यावरणीय क्षति बढ़ेगी और सुरक्षा की समस्या उत्पन्न होगी।
 4. साथ ही अवगत कराना है कि 06 हेक्टेयर के सेफ्टी जोन हेतु कुल 45.00 लाख रुपये प्रभागीय वनाधिकारी, सिंगरौली वन मंडल में जमा किये जा चुके हैं जिसमें कुल 18 लाख रुपये फेंसिंग निर्माण, सुरक्षा एवं पुनरुत्पादन बनाये रखने के लिए SBI DD No. 211008 दिनांक 29.10.2009 एवं कुल 27 लाख रुपये सेफ्टी जोन क्षेत्र रकबा 6 हेक्टेयर का डेढ़ गुना 09 हेक्टेयर क्षेत्रफल के समतुल्य अन्य बिगड़े वन क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण के व्यय हेतु SBI Bank DD No. 210210 दिनांक 06.10.2009 द्वारा जमा किये गए हैं।
 5. हालांकि 20 MTPA की खनन योजना के अनुसार खदान क्षेत्र के भीतर पूरे जीवन के दौरान कुल 1415 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण किया जाएगा।
9. Given the density of 0.5 of the 53.142 ha forest land, number of project affected trees reported as 27342 appears to be have been estimated on lower side as the proposed area is having Very Dense Forest (VDF) & Moderately Dense Forest (MDF) based on DSS analysis. Therefore, same needs to be reconfirmed by the State.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में वन मंडल अधिकारी सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/3630 दिनांक 05.06.2024 से प्रतिवेदित किया गया है कि पी.एफ. 261 का मौका स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित उक्त वनभूमि के वृक्षों की गणना अनुसार कुल 6 सैम्पल प्लॉट डालकर गणना किये जाने पर प्रति हेक्टेयर 514.5 वृक्ष पाये गये हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर के अनुसार कुल रकबा 53.142 हेक्टेयर में 27342 वृक्ष पाये गये हैं शेष स्थल में 20-20 सेंटी मीटर से नीचे गर्थ क्लास के स्थापित पौधे बहुतायत मात्रा में मौके पर उपलब्ध हैं। 20 सेंटी मीटर के नीचे गोलाई वर्ग के वृक्ष स्थापित पौधे नवअंकुरण बहुतायत मात्रा में होने से सेटेलाईट से देखने पर घना वनक्षेत्र दिखाई देता है।

10. It has been reported that the mining operation have been started and date back to year 1981-82 in the Khadia Project and further, as per Part-I of the application, total forest existing within the Mining lease is found to be 901.906 ha. In this regard, copies of approval obtained by the user agency in different time span under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 needs submission.

उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खड़िया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट की 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष की अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खदान क्षेत्र में कुल वनभूमि 904.765 हेक्टेयर है। 20 MTPA की खनन योजना की प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में संलग्न है।

खड़िया ओपन कास्ट खदान क्षेत्र में आने वाली वनभूमि के सम्बन्ध में जारी वन स्वीकृतियों की प्रतियां Annexure-C पर संलग्न हैं इन वन स्वीकृतियों के विवरण निम्नलिखित हैं:-

1. उत्तर प्रदेश में 1305.00 हेक्टेयर वनभूमि वन स्वीकृति (खड़िया और चुधीचुआ ओसीपी, मेसर्स एनसीएल को संयुक्त रूप से जारी) पत्र संख्या 8-298/87-FC Dated 30.7.1990 के माध्यम से जारी की गई ।
2. मध्य प्रदेश में 180.00 हेक्टेयर वनभूमि की वन स्वीकृति खड़िया ओसीपी को पत्र संख्या 8-85/2005-FC Dated 14.09.2010 के माध्यम से जारी की गई ।
3. मध्य प्रदेश में 378.935 हेक्टेयर वनभूमि की वन स्वीकृति बीना एक्सटेंशन ओसीपी मेसर्स एनसीएल को पत्र संख्या 8-58/2005-FC Dated 13.08.2007 के माध्यम से जारी की गई है जिसमें से 7.623 हेक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण खड़िया एक्सटेंशन ओसीपी के पक्ष में प्रक्रिया में है।

11. As per the Mining plan, it has been reported that numerous seasonal nalas flowing through this area and meet the master drain the Rihand dam (Govind Ballabh Pant Sagar) which is located south of this area. Tippa Jharia nala drains the Khadia (Expansion) OCP area in north and Ballia nalla drains this OCP in south and meet the Gobind Ballabh Pant Sagar. Therefore, comments of the water resource department on the proposed measures and impact of the project on the hydrological regime are required to be submitted.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौसमी नाले के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु विस्तृत योजना तैयार कर ली गई है तथा प्रस्तावित उपायों एवं प्रभावों पर जल संसाधन विभाग, सिंगरौली की टिप्पणियों पत्र क्रमांक 671/तकनीकी/2024 दिनांक 27.04.2024 द्वारा प्राप्त कर ली गई है । जल संसाधन विभाग सिंगरौली को प्रस्तुत योजना की प्रति और प्राप्त टिप्पणियों Annexure-D & E पर संलग्न हैं।

12. As per the present land use given in the Mining plan, forest area within the lease is reported as 57.906 ha whereas the 53.142 ha forest land has been sought through instant proposal. This variation needs clarification.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पूर्व में 57.906 हेक्टेयर वन स्वीकृति प्राप्त करने के लिए निर्धारित की गई थी। हालांकि विस्तृत जाँच के बाद यह पाया गया कि रकबा 57.906 हेक्टेयर का एक भाग जो पहले खनन योजना के विस्तार हेतु लिया गया था, पहले से ही बीना एक्सटेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के कब्जे में है (FC No. पत्र संख्या 8-58/2005-FC Dated 13.08.2007 के माध्यम से) और उस भूमि का खड़िया एक्सटेंशन ओसीपी के पक्ष में हस्तान्तरण प्रक्रिया में है। बीना एक्सटेंशन ओसीपी से खड़िया एक्सटेंशन ओसीपी के लिए 7.623 हेक्टेयर वनभूमि के हस्तान्तरण के लिए आवेदन की प्रति Annexure-F के रूप में संलग्न है।

इसे 20 एमटीपीए की अनुमोदित संशोधित खनन योजना में शामिल किया गया है जिसकी प्रति ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड की गई है।

13. The State Government has proposed degraded forest land (DFL) for CA in the instant proposal. However, as per Para (1) of the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 incorporated in Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023 issued by the Ministry on dated 29.12.2023 says that "an user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising compensatory afforestation over such land". Therefore the User agency shall provide the details of non-forest land for raising compensatory afforestation along with KML file and required documents.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि :-

खड़िया ओसीपी, एनसीएल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर जिला कलेक्टर, दमोह मध्य प्रदेश द्वारा प्रभावित रकबा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जिला दमोह तहसील पटेरा ग्राम मौजा धुघरी प.ह.न.54 खसरा नम्बर 73 की रकबा 53.142 हेक्टेयर मद पहाड़ गैरवनभूमि पत्र क्रमांक RCMS/002/ (अ) - 20(3)/24-25 दिनांक 12.06.2024 से वन विभाग को हस्तान्तरित करने का आदेश पत्र जारी किया गया है जो Annexure-G पर संलग्न है।

चूंकि उपयोगकर्ता एजेंसी प्रतिपूरक वनीकरण के विवरण को संशोधित करने में असमर्थ है और अतिरिक्त जानकारी में KML File अपलोड नहीं की जा सकती है इसलिए पहचान की गई गैर वनभूमि KML File सॉफ्ट कॉपी में संलग्न है।

डीजीपीएस मानचित्र, भारत सरकार सर्वेक्षण के टोपोशीट पर सीमांकन और प्रभागीय वनाधिकारी, दमोह द्वारा जारी की गई स्थल उपयुक्तता पत्र Annexure-G पर संलग्न है।

14. The user agency shall upload the KML file of the proposed diversion area as per the component wise break-up given in online form.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि component wise break-up KML file ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर दी गई है।

15. The user agency has uploaded the KML file of Mining lease boundary and its total area is found to be 1697.906 ha and a part of the Mining lease area is also located in the Uttar Pradesh State. Further in the said Mining lease KML file, the user agency has excluded some portion falling in the forest land and reason for such deletion is not available in the proposal. This needs clarification.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:-

1. कुल खनन क्षेत्र 1697.906 हेक्टेयर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है।
2. कुल खनन क्षेत्र में से 664.00 हेक्टेयर वनभूमि उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसके लिए वन स्वीकृति पत्र संख्या 8-298/87-FC Dated 30-07-1990 के माध्यम से प्राप्त है (खड़िया और दुधीचुआ ओसीपी, मेसर्स एन.सी.एल को संयुक्त रूप से जारी की गई)
3. कुल खनन क्षेत्र में से 240.765 हे. वनभूमि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसके लिए 180.00 हे. की वन स्वीकृति पत्र संख्या 8-58/2005-FC Dated 14-09-2010

के माध्यम से जारी की गई है। बीना एक्सटेंशन ओसीपी को पत्र संख्या 8-58/2005-FC Dated 13-08-2007 के माध्यम से जारी 378.935 हेक्टेयर की वन स्वीकृति से 7.623 हेक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण प्रक्रिया में है और वर्तमान आवेदन 53.142 हेक्टेयर के लिए किया गया है।

4. अनावेदित क्षेत्र (7.623 हेक्टेयर) को बीना एक्सटेंशन ओसीपी से स्थानांतरित किया जाना है, जिसके लिए बीना एक्सटेंशन ओसीपी को पत्र संख्या 8-58/2005-FC Dated 13-08-2007 के माध्यम से वैद्य वन स्वीकृति प्राप्त है। बीना एक्सटेंशन ओसीपी से खड़िया एक्सटेंशन ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के लिए इस 7.623 हेक्टेयर वनभूमि का हस्तान्तरण प्रक्रिया में है। (हस्तान्तरण आवेदन की प्रति Annexure-F पर संलग्न है।

16. Out of 1697.906 ha area of the Mining lease, total forest land reported in the lease is 901.906 ha. Out of this 901.906 ha forest land majority part is located in the Uttar Pradesh State. This needs justification. Therefore, the user agency/state shall provide the complete/correct KML file of eforest land in the lease.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में आवेदक संस्था द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 20 एमटीपीए की संशोधित खनन योजना अनुसार कुल रकबा 1697.906 हेक्टेयर क्षेत्र में 904.765 हेक्टेयर क्षेत्र वनभूमि है। रकबा 904.765 हे. मे से 664.00 हेक्टेयर वनभूमि क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है, जिसकी भारत सरकार पर्यावरण वन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा पत्र क्रमांक 8-298/87-FC दिनांक 30.07.1990 से स्वीकृति प्रदान की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य की 664.00 हे. की और मध्य प्रदेश राज्य की रकबा 180.00 हेक्टेयर, रकबा 7.623 हेक्टेयर एवं रकबा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि की KML File ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 के अनुक्रमांक- C (a) (1), (2), (3), & (4) पर अपलोड की गई है।

17. As per DSS analysis the total forest land within the State of Madhya Pradesh is found to be 242.574 ha. Further out of this 242.574 ha forest land, the user agency has taken approval under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for an area of 180 ha and submitted the instant diversion proposal for an area of 53.142 ha. Hence, the status of balance 9.432 ha forest land needs submission.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाहरी सीमा के KML File को ठीक कर लिया गया है और मध्यप्रदेश राज्य के भीतर वनभूमि रकबा 240.765 हेक्टेयर है जिसमें खड़िया परियोजना रकबा 180.00 हेक्टेयर वनभूमि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 14.09.2010 से प्रदान की जा चुकी है। बीना एक्सटेंशन परियोजना रकबा 378.935 हेक्टेयर वनभूमि की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा पत्र दिनांक 13.08.2007 से एन.सी.एल. की बीना यूनिट को प्रदान की गई है में से रकबा 7.623 हेक्टेयर वनभूमि एन.सी.एल. की बीना यूनिट से खड़िया यूनिट को हस्तान्तरित करने का प्रस्ताव प्रचलित है। तथा यह खड़िया परियोजना रकबा 53.142 हेक्टेयर वनभूमि प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रक्रियारत है

18. The user agency is submitting the proposal for diversion of forest land in piecemeal. The reasons for the same needs submission.

इस बिन्दु के सम्बन्ध में इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:-

1. 180.00 हेक्टेयर की वन स्वीकृति खड़िया ओपन कास्ट प्रोजेक्ट के 4 मिलियन टन प्रति वर्ष से 10 मिलियन टन प्रति वर्ष तक विस्तार के लिए प्राप्त की गई थी। वर्तमान विस्तार खड़िया ओसीपी को 20 एमटीपीए तक विस्तार के लिए की जा रही है।
2. उपर्युक्त विवरण के अनुसार, कुल 904.765 हेक्टेयर में से :-
उत्तर प्रदेश राज्य में 664.00 हे. के लिए वन स्वीकृति प्राप्त की गई है।
मध्यप्रदेश राज्य में 180.00 हे. के लिए वन स्वीकृति प्राप्त की गई है और 7.623 हेक्टेयर बीना एक्सटेंशन ओसीपी से स्थानांतरित किया जा रहा है, तथा शेष 53.142 हे. वनभूमि के लिए वन स्वीकृति प्राप्त की जा रही है।
3. इस 53.142 हे. वनभूमि के अलावा कोई अन्य वनभूमि नहीं है, जिसे वन स्वीकृति की आवश्यकता हों।

19. The area proposed for diversion is having high biological richness as per DSS analysis. The justification for proposing such biodiversity rich area for mining shall be submitted. Also the State Govt. shall submit the status of unbroken area available in the vicinity of the proposed diversion and within the mining lease area.

इस बिन्दु के इस बिन्दु के सम्बन्ध में उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि:-

1. प्रस्तावित वनभूमि जिसके लिए आवेदन किया गया है, वह कोयला युक्त क्षेत्र है और अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार से अतिरिक्त लगभग 35.46 मिलियन टन कोयला निकाला जाएगा। कोयला खनन एक स्थल विशेष गतिविधि है और भूमि को कोयला क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचित किया गया है।
2. खड़िया ओसीपी के आसपास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है क्योंकि खड़िया ओसीपी पश्चिम दिशा में दुधीचुआ ओसीपी, पूर्व दिशा में कृष्णाशिला ओसीपी और उत्तर-पूर्व दिशा में बिना एक्सटेंशन ओसीपी से घिरा हुआ है।
3. दिनांक 01.07.2024 तक, खदान क्षेत्र के भीतर लगभग 110.63 हेक्टेयर (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य सहित) कोयला युक्त भूमि उपलब्ध है, जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

भूमि का प्रकार	मध्यप्रदेश राज्य में खदान क्षेत्र के भीतर (हे. में)	उत्तर प्रदेश राज्य में खदान क्षेत्र के भीतर (हे. में)
वनभूमि	49.17	41.88
गैर वनभूमि	0.00	19.58
कुल	49.17	61.46

अतः उपरोक्तानुसार जानकारी संलग्न प्रेषित कर प्रकरण में स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक / F-1/FP/MP/MIN/149270/2021/
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त रीवा, मध्यप्रदेश ।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मंडल सिंगरौली, मध्यप्रदेश ।
3. महाप्रबंधक, नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड, खड़िया परियोजना सिंगरौली म.प्र. ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन संरक्षक रीवा वन वृत्त रीवा

केन्द्रीय विद्यालय रोड वन विश्राम गृह जयंती कुंज रीवा म0प्र0
Phone No.07662- 299198, 297335 E-mail-ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक/मा.चि./2024/6121
प्रति ,

रीवा दिनांक 30.07.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)
वन भवन, तुलसीनगर
भोपाल म0प्र0

विषय:- वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के वन कक्ष पीएफ-261 रकबा 53.142 हे. वन भूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अन्तर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का-एन.सी.एल. का ऑन लाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/149270/2021

संदर्भ:- 1. आपका पत्र क्र./एफ-1/FP/MP/MIN/149270/2021 दि. 06.03.2024
2. व0म0अ0 सिंगरौली का पत्र क्रमांक/तक/4511 दिनांक 16.07.2024

-----000-----

विषयान्तर्गत निवेदन है कि आपके द्वारा पत्र क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/149270/2021 दिनांक 06.03.2024 से 19 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई थी।

वन मण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा आवेदक संस्थान से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर वन मण्डल स्तर की जानकारी सहित संदर्भित पत्र-2 से इस कार्यालय को प्रेषित की गई है।

अतः वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल सिंगरौली से प्राप्त जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(राजेश कुमार राय)
भा.व.से.

वन संरक्षक

29/7/24 रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/6122
प्रतिलिपि-

रीवा दिनांक 30.07.2024

1. वन मण्डलाधिकारी, वन मण्डल सिंगरौली की ओर सूचनार्थ।
2. महाप्रबंधक, खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड, पोस्ट खड़िया, जिला सोनभद्र, (उत्तर प्रदेश) की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक

रीवा वृत्त, रीवा म.प्र.

29/7/24



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0) सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में
ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र०/तक०/५५११
प्रति,

बैठन, दिनांक 16.07.2024

- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल
- विषय:- वन मण्डला सिंगरौली के परिक्षेत्र बैठन के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 261 के रकवा 53.142 हे० वन भूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अन्तर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का एनसीएल का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र० FP/MP/MIN/149270/2021
- संदर्भ:- 1. आपका पत्र कमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/149270/2021/1463 भोपाल दिनांक 06.03.2024
2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 28.02.2024
3. महाप्रबंधक एन.सी.एल खड़िया परियोजना का पत्र कमांक/4367 दिनांक 09.07.2024

-000-

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) के तहत नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड खड़िया परियोजना में माइनिंग हेतु प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैठन अन्तर्गत कक्ष कमांक पी.एफ. 261 कुल रकवा 53.142 हे० वन भूमि प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र (1) से भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परियोजना के संबंध में 19 बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है। जिसमें बिन्दु कमांक 2 एवं 9 की जानकारी तैयार कर कार्यालयीन पत्र कमांक/तक०/3630 दिनांक 05.06.2024 को प्रेषित किया गया है, जिसमें बिन्दु कमांक 2 में वैकल्पिक वृक्षारोपण की के०एम०एल० फाईल संलग्न है।

सन्दर्भित पत्र (3) से आवेदक संस्थान से संबंधित जानकारी ऑनलाईन प्रस्ताव के भाग-1 में अपलोड कर एवं हार्ड कॉपी में प्राप्त कर एवं बिन्दु कमांक 13 से प्राप्त समतुल्य गैर वनभूमि की के०एम०एल० फाईल मूलतः संलग्न कर आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

बैठन, दिनांक 16.07.2024

पृ०क्र०/तक०/५५१२

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का

माजुन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल-dfot.sgl@mp.gov.in, फोन-07805-233336 फैक्स-233335

अधिकार

क्र०/तक०/3630
प्रति,

बैठन, दिनांक 05.06.2024

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय:-

वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैठन के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 261 के रकवा 53.142 हे० वन भूमि में खड़िया विस्तार परियोजना अन्तर्गत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का एनसीएल का ऑनलाईन प्रस्ताव क्र० FP/MP/MIN/149270/2021

संदर्भ:-

1. आपका पत्र कमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/149270/2021/1463 भोपाल दिनांक 06.03.2024
2. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 28.02.2024

-000-

विषयांतर्गत के संबंध में वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) के तहत नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड खड़िया परियोजना में माइनिंग हेतु प्रस्तावित है। जिसमें वन परिक्षेत्र बैठन अन्तर्गत कक्ष कमांक पी.एफ. 261 कुल रकवा 53.142 हे० वन भूमि प्रस्तावित है।

सन्दर्भित पत्र (1) से लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 28.02.2024 से परियोजना के संबंध में 19 बिन्दुओं की जानकारी चाही गयी है। जिसमें बिन्दु कमांक 2 एवं 9 की जानकारी तैयार करने हेतु लेख किया गया है, जो उप वन मण्डल अधिकारी बैठन से प्राप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

बिन्दु कमांक 2 के संबंध में :-

क्र.	योजना का नाम	परिक्षेत्र का नाम	रोपण वर्ष	बीट का नाम/कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हे० में)	रोपित पौधों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	एन.सी.एल.	माड़ा	2014	माड़ा, आर. 540	60	60000
2	खड़िया विस्तार			सिद्धी आर. 424	50	50000
3	परियोजना			धनगढ़ आर. 553	50	50000
4	अंतर्गत			बिन्दुल आर. 551	50	50000
5	वैकल्पिक			धरी आर. 453	50	50000
6	वृक्षारोपण वर्ष			डोंगरी आर. 515	50	50000
7	2013-14	पूर्व सरई	2014	देवरी आर. 320	50	50000
योग:-					360	360000

बिन्दु कमांक 9 के संबंध में मौका स्थल पी.एफ. 261 का निरीक्षण किया गया, पाया गया कि पूर्व में प्रस्तावित उक्त वन भूमि के वृक्षों की गणना अनुसार कुल 6 प्लाट डालकर गणना किये जाने पर प्रति हेक्टेयर 514.5 वृक्ष पाये गये हैं, जिसमें प्रति हेक्टेयर के अनुसार कुल रकवा 53.142 हे० में 27342 हे० वृक्ष पाये गये हैं। शेष स्थल में 20-20 से०मी० से नीचे गर्त क्लास के स्थापित पौधे बहुतायत मात्रा में मौके में उपलब्ध हैं। 20 से०मी० के नीचे गोलाई वर्ग के वृक्ष स्थापित पौधे नवअंकुरण बहुतायत मात्रा में होने से सेटेलाईट से देखने पर घना वन क्षेत्र दिखाई देता है।

अतः उक्त चाही गयी बिन्दु कमांक 2 एवं 9 की जानकारी आपकी ओर सादर सम्प्रेषित है।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

बैठन, दिनांक 05.06.2024

पृ०क्र०/तक०/363)

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. महाप्रबंधक खड़िया परियोजना नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड की ओर सूचनार्थ।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली



कार्यालय वन मण्डल अधिकारी वन मण्डल सिंगरौली(म0प्र0)

सूचना का

माजन मोड़ जिला पंचायत के बगल में

ईमेल—dfot.sgl@mp.gov.in, फोन—07805-233336 फैक्स—233335

अधिकार

क्र0/तक0/4517

सिंगरौली, दिनांक. 16-07-2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध) म0प्र0 भोपाल

विषय:— Staus of plantation activity on 360 ha. Forest land as CA against 180 ha.
Forest land diverted to Khadia Project NCL.

सन्दर्भ:— आपका पत्र क्रमांक/एफ—1/FP/MP/MIN/149270/1463 भोपाल दिनांक 06.03.2024

—000—

विषयांतर्गत सन्दर्भित पत्र के द्वारा एन.सी.एल. खड़िया प्रोजेक्ट में 180 हे0 प्रभावित वनभूमि के बदले 360 हे0 वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी चाही गई है।

उक्त प्रोजेक्ट के अंतर्गत वन मण्डल सिंगरौली में कुल 360 हे0 वनभूमि में वर्ष 2013-14 में क्षेत्र तैयारी का कार्य एवं वर्ष 2014-15 में वैकल्पिक वृक्षारोपण का कार्य कराया गया है। उक्त वृक्षारोपण परियोजना की अवधि 10 वर्षीय थी जो कि वर्ष 2022-23 में पूर्ण हो चुकी है। पौधों की वृद्धि एवं जीवितता कैम्पा के नियमानुसार है।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

सिंगरौली दिनांक 16-07-2024

पृ0क्र0/तक0/4518

प्रतिलिपि:— वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा म0प्र0 की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

वन मण्डल अधिकारी

वन मण्डल सिंगरौली

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
खडिया परियोजना
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Office of General Manager

Northern Coalfields Limited
Khadia Project
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

थाना-शक्तिनगर, जनपद-सोनभद्र (उ. प्र.), पिन - 231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonbhadra (U.P.) Pin- 231222
Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: cgm.khd@gmail.com, website : www.ncil.in

Ref: NCL/KHD/GM/Min/Env/FC 53.142 Ha/2024-25/4867

Date: 09/07/2024

To,
Divisional Forest officer,
Singrauli Forest Division
MP Forest Department,
Singrauli

Subject:- Diversion of 53.142 Ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh State (Online No FP/MP/MIN/149270/2021)

Ref:- (i) Online proposal no. FP/MP/MIN/149270/2021

(ii) EDS raised by AIG (Forest), MoEF&CC, New Delhi vide letter dated 28.02.2024.

(iii) Letter issued by APCCF (Land Management), MP, Bhopal vide letter no. F-1/FP/MP/MIN/149270/2021/1463 dated 06.03.2024.

(iv) EDS raised by DFO, Singrauli on 14.03.2024

Respected Sir,

In reference to the above, this is to submit that an EDS was raised by AIG (Forest), MoEF&CC, New Delhi in the online proposal for Diversion of 53.142 Ha forest land in compartment No PF-261, Waidhan Range of Singrauli Forest Division for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project by M/s Northern Coalfields Ltd. (NCL) under Singrauli District of Madhya Pradesh State, vide letter 28.02.2024.

In connection with the above letter, APCCF (Land Management), MP, Bhopal vide letter no. F-1/FP/MP/MIN/149270/2021/1463 dated 06.03.2024 raised query to your good office for reply of queries raised by MoEF&CC, New Delhi. As per the letter, reply of query of point no. i, iii, iv, vii, viii, ix, x, xi, xii, xiii, xiv, xv, xvi, xvii, xviii and xix was to be provided by Khadia Project and reply of query no. ii and ix was to be provided by your good office.

Point wise reply of the queries raised by MoEF&CC, New Delhi vide letter dated 28.02.2024 is enclosed herewith.

It is requested to kindly consider the replies submitted and forward the online proposal with kind reply of point no. ii and ix of the letter issued by AIG Forest, MoEF&CC, New Delhi dated 28.02.2024.

Encl:- As above.

Yours faithfully,

General Manager
Khadia Area, NCL

Northern Coalfields Limited
Khadia Area

Point wise reply of the queries raised by MoEF&CC, Delhi on 28.02.2024 in the Forest clearance application of 53.142 Ha required for Expansion of Khadia OCP.


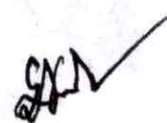
Sl. No.	Query	Reply
i.	The State Govt. has mentioned that the proposal is for Khadia Expansion Open Cast Coal Mine Project and as per records available on Parivesh portal it has been found that the Ministry vide letter No 8-85/2005-FC dated 14.09.2010 has approved diversion of 180 ha forest land for Khadia Project of Northern Coalfields Limited (NCL) in Sidhi District. Therefore the compliance of conditions stipulated in said approval needs submission.	Compliance status of the conditions stipulated in Forest Clearance issued for 180 Ha vide letter No 8-85/2005-FC dated 14.09.2010 is enclosed herewith as Annexure-A.
ii.	Present status of Compensatory Afforestation (CA) which was then approved in case of 180 ha diverted forest land needs submission along with the KML files.	Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P.
iii.	Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Progressive Mine Closure Plans and gaps if any, shall be intimated by the State.	Till 31.03.2024, biological reclamation has been done on 208.89 Ha on overburden dumps and 156.5 Ha in plain areas, i.e, total 365.39 Ha has been reclaimed, which is in line with the approved mining plan and mine closure plan prepared for 20 MTPA. As per approved Mine Closure Plan of 20 MTPA, the target for plantation as on 31.03.2024 was 365 Ha and actual plantation as on date is 365.39 Ha.
iv.	Cost Benefit analysis indicating the CB ratio of 1:121.306 has been submitted which appears to be exorbitantly high. The same needs to be revisited and estimated using appropriate techno-economic tools for estimation of all parameters and their discounting to arrive at same values of cost and future benefits as per prescribed format.	As per instruction, the Cost Benefit analysis has been reviewed, now revised CB ratio comes to 1:82.19. The revised Cost Benefit analysis has been enclosed herewith as Annexure B and has also been updated at Part-I of the application.
v.	The State Govt. reported that the proposed forest land for diversion is located within 1 Km from the Wildlife	Reply to this point may be arranged by Forest Department, State Govt. of M.P.

Sl. No.	Query	Reply
	Sanctuary/ National park/ Biosphere Reserve/ Tiger Reserve/ Elephant corridor. However, specific details have not been submitted. Therefore, the comments of the CWLW in this regard and status of wildlife clearance needs submission.	However, the As per part-II of the application duly filled by DFO, Singrauli, there is no Wildlife Sanctuary/ National park/ Biosphere Reserve/ Tiger Reserve/ Elephant corridor within 01 Km from the proposed diversion.
vi.	The State Govt. shall clarify whether the present proposal requires Wildlife Management plan or otherwise	<p>Reply to this point may be arranged by Forest Department, State Govt. of M.P.</p> <p>However, "<i>Integrated Wildlife Plan of Singrauli Region</i>" was prepared by NCL through Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal in the year 2020 and submitted to Forest Department, State Govt. of MP. In compliance of the instruction from Forest Department, State Govt. of MP, an amount of Rs. 21.34 Cr as per the plan was deposited in CAMPA Account vide UTR No. SBINR52020122303364518 on 23.12.2020.</p>
vii.	Details of coal evacuation plan and involvement/requirement of additional forest land, if any, shall be intimated.	<p>As per the approved Mining Plan for 20 MTPA capacity, the coal evaluation of the Khadia OCP will be as follows:</p> <p>"Coal dispatch of produced coal of 20 MTPA by Khadia Expn. OCP (20 MPTA) will be handled by existing CHP of capacity 10.00 Mtpa and an upcoming 4 Mtpa CHP with RLS. Balance coal will be handled by existing Krishnashila CHP, wharfwall and proposed western stream of CHP. A part of the above mechanism coal may be dispatched by road as per the Govt. guidelines."</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No additional forest land is required by Khadia Expansion Opencast Project for the purpose of coal evacuation.
viii.	Satellite imagery shows that safety zone in the Khadia and the adjoining mine has not been maintained. The State Govt. shall submit the justification along with the status of safety zone maintained in the mined out area.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mines adjoining to Khadia Opencast Project are Dudhichua OCP and Krishnashila OCP of the same owner i.e. M/s. Northern Coalfields Limited located in the West side in the East side respectively. ▪ The coal seams namely Purewa Top, Purewa Bottom and Turra of Singrauli coalfields are lying continuous. Khadia

3

gln

Sl. No.	Query	Reply
		<p>OCP and its adjacent mines namely Krishnashila OCP & Dudhichua OCP are operating on the same continuing seams. The adjoining mines extract coal in sequential operation at barrier so as to extract maximum coal. Plantation at this stage shall sterilize 36 Million Tonne of coal, which will be against the principal of resource optimisation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Further, any coal left shall catch fire due to spontaneous heating which shall further aggravate environmental damage and will create Safety hazard. Further, it is to state that for the purpose of safety zone of 06 Ha, Rs. 45.00 Lakhs has been deposited to DFO Singrauli, MP Forest Department vide SBI DD No.211008 dated 29.10.2009 for Rs. 18 Lakhs required for fencing construction, safety and regeneration of safety zone plantation and vide SBI Bank DD No. 210210 dated 06.10.2009 for Rs. 27 lakhs, required for plantation of 1.5 times of the safety zone area (1.5 time of 06 Ha i.e. 09 Ha) at other degraded area. However, as per Mining Plan of 20 MTPA, plantation will be carried out over total 1415 Ha area within mine area throughout the balance life.
ix.	<p>Given the density of 0.5 of the 53.142 ha forest land, number of project affected trees reported as 27342 appears to be have been estimated on lower side as the proposed area is having Very Dense Forest (VDF) & Moderately Dense Forest (MDF) based on DSS analysis. Therefore, same needs to be reconfirmed by the State</p>	<p>Reply to this point may be arranged by Forest Department, Singrauli, M.P.</p>
x.	<p>It has been reported that the mining operation have been started and date back to year 1981-82 in the Khadia Project and further, as per Part-I of the application, total forest existing within the Mining lease is found to be</p>	<ul style="list-style-type: none"> As per approved Mining Plan of 20 MTPA of Khadia OCP, the total forest land involved in the mine lease area is 904.765 Ha (Copy of mining plan of 20 MTPA is enclosed in part-I of the application).

Sl. No.	Query	Reply
	901.906 ha. In this regard, copies of approval obtained by the user agency in different time span under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 needs submission.	<ul style="list-style-type: none"> The copies of Forest Clearances issued w.r.t. forest land falling within the leasehold area of Khadia OCP are enclosed herewith as Annexure-C. Details of these FCs are as follows : <ol style="list-style-type: none"> Forest Clearance of 1305 Ha forest land in Uttar Pradesh (combinedly issued to Khadia and Dudhichua OCP of M/s NCL) issued vide letter no. 8-298/87-FC dated 30.07.1990. Forest Clearance of 180 Ha forest land in Madhya Pradesh issued to Khadia OCP vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010. Forest Clearance of 378.935 Ha forest land in Madhya Pradesh issued to Bina Extension OCP of M/s NCL vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007, out of which transfer of 7.623 ha forest land in favour of Khadia Expansion OCP is in process.
xi.	As per the Mining plan, it has been reported that numerous seasonal nallas flowing through this area and meet the master drain the Rihand dam (Govind Ballabh Pant Sagar) which is located south of this area. Tippa Jharla nala drains the Khadia (Expansion) OCP area in north and Ballia nalla drains this OCP in south and meet the Gobind Ballabh Pant Sagar. Therefore, comments of the water resource department on the proposed measures and impact of the project on the hydrological regime are required to be submitted.	The detailed plan for conservation and protection of seasonal nallah has been prepared and comments of Water Resource Department, Singrauli (M.P.) on proposed measures and impacts has been obtained vide letter no 671/ तकनीकी/2024 dated 27.04.2024. Copy of plan submitted to Water Resource Department, Singrauli (M.P.) and comments received are being enclosed as Annexure D and Annexure E respectively.
xii.	As per the present land use given in the Mining plan, forest area within the lease is reported as 57.906 ha whereas the 53.142 ha forest land has been sought through instant proposal. This variation needs clarification	<ul style="list-style-type: none"> As per the Project Report, earlier 57.906 Ha was assessed to be obtain Forest Clearance. However, after detailed scrutiny, it was found that a part portion of 57.906 Ha earlier identified in Mining Plan, is already under the possession of the Bina Extension Opencast Project (vide FC no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007) and transfer of that land in favour of Khadia Expansion OCP is in process. Copy of the application for transfer of 7.623 Ha forest land from Bina extension OCP to Khadia

Sl. No.	Query	Reply
		<p>Expansion OCP is enclosed herewith as Annexure -F.</p> <ul style="list-style-type: none"> The same has been incorporated in approved revised Mining Plan of 20 MTPA and copy of the same is enclosed at part-I of the application.
xiii.	<p>The State Government has proposed degraded forest land (DFL) for CA in the instant proposal. However, as per Para (1) of the Rule-13 of the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Rules, 2023 incorporated in Consolidated Guidelines and Clarifications issued under Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 2023 issued by the Ministry on dated 29.12.2023 says that "an user agency shall provide land which is neither notified as forest under the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) or any other law nor managed as forest by the Forest Department and it shall also bear the cost of raising compensatory afforestation over such land". Therefore the User agency shall provide the details of non-forest land for raising compensatory afforestation along with KML file and required documents</p>	<ul style="list-style-type: none"> On the basis of application submitted by Khadia OCP, NCL, the letter for allocation of 53.142 Ha non-forest land (Govt. Land) to Forest Department, Madhya Pradesh has been issued by District Collector, Damoh (MP) vide letter no. RCMS/002/(3F)-20(3)/24-25 dated 12.06.2024 for raising compensatory afforestation at Khasra No. 73, Village- Ghughri, Tehsil-Patera, District- Damoh, Madhya Pradesh (Copy enclosed as Annexure-G) As user agency is unable to modify the details of compensatory afforestation and KML file can not be uploaded in additional information, KML file of the identified non forest land is enclosed herewith in soft copy in enclosed Compact Disc (CD). DGPS Map, demarcation on Survey of India Toposheet and Site suitability report duly issued by DFO, Damoh are enclosed as Annexure-H, I & J.
xiv.	<p>The user agency shall upload the KML file of the proposed diversion area as per the component wise break-up given in online form.</p>	<p>Component wise KML file of proposed diversion area has been uploaded in Part-1 of Form A at Parivesh portal.</p>
xv.	<p>The user agency has uploaded the KML file of Mining lease boundary and its total area is found to be 1697.906 ha and a part of the Mining lease area is also located in the Uttar Pradesh State. Further in the said Mining lease KML file, the user agency has excluded some portion falling in the forest land and reason for such deletion is not available in the proposal. This needs clarification.</p>	<ul style="list-style-type: none"> The total leasehold area of 1697.906 ha lies in both Madhya Pradesh and Uttar Pradesh States. 664 Ha forest land out of total lease area lies in Uttar Pradesh State for which Forest Clearance has been obtained vide letter no. 8-298/87-FC dated 30.07.1990 (combinedly issued to Khadia and Dudhichua OCP of M/s. NCL). 240.765 Ha forest land out of total lease area lies in Madhya Pradesh state, for which, Forest Clearance of 180 Ha has

Sl. No.	Query	Reply															
		<p>been obtained vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010, transfer of forest land of 7.623 ha from Forest Clearance of 378.935 Ha issued to Bina Extension OCP vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007 is in process and present application has been made for 53.142 Ha.</p> <p>The area excluded to be applied (7.623 Ha) is the area which is to be transferred from Bina Extension OCP, for which Bina Extension OCP has valid Forestry Clearance vide FC no. letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007. The transfer of this 7.623 Ha forest land from Bina extension OCP to Khadia Expansion Opencast Project is in progress (Copy of transfer application is enclosed as Annexure-F)</p>															
xvi.	<p>Out of 1697.906 ha area of the Mining lease, total forest land reported in the lease is 901.906 ha. Out of this 901.906 ha forest land majority part is located in the Uttar Pradesh State. This needs justification. Therefore, the user agency/state shall provide the complete/correct KML file of forest land in the lease.</p>	<ul style="list-style-type: none"> As per approved revised Mining Plan of 20 MTPA, forest land in total 1697.906 Ha area is 904.765 Ha. Out of 904.765 Ha, 664 Ha forest land area lies in Uttar Pradesh state, for which Forest Clearance has been obtained vide letter no. 8-298/87-FC dated 30.07.1990. KML file for forest land of 664 Ha in Uttar Pradesh state and 180 Ha, 7.623 Ha & 53.142 Ha in Madhya Pradesh state has been enclosed at part-I of the application. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sl. No.</th><th>Forest land details</th><th>Location in application</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>664 Ha in UP state</td><td>C(a)(2)</td></tr> <tr> <td>2</td><td>180 Ha in MP</td><td>C(a)(3)</td></tr> <tr> <td>3</td><td>7.623 Ha in MP</td><td>C(a)(4)</td></tr> <tr> <td>4</td><td>53.142 Ha in MP</td><td>C(a)(1)</td></tr> </tbody> </table>	Sl. No.	Forest land details	Location in application	1	664 Ha in UP state	C(a)(2)	2	180 Ha in MP	C(a)(3)	3	7.623 Ha in MP	C(a)(4)	4	53.142 Ha in MP	C(a)(1)
Sl. No.	Forest land details	Location in application															
1	664 Ha in UP state	C(a)(2)															
2	180 Ha in MP	C(a)(3)															
3	7.623 Ha in MP	C(a)(4)															
4	53.142 Ha in MP	C(a)(1)															
xvii.	<p>As per DSS analysis the total forest land within the State of Madhya Pradesh is found to be 242.574 ha. Further out of this 242.574 ha forest land, the user agency has taken approval under the Van (Sanrakshan Evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 for an area of 180 ha and submitted the</p>	<p>The KML of outer boundary has been corrected and the forest land within Madhya Pradesh state is 240.765 Ha, details of which is as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> Forest Clearance for 180 Ha obtained vide letter no. 8-85/2005-FC dated 14.09.2010. 															

[Handwritten signature]

Sl. No.	Query	Reply						
	instant diversion proposal for an area of 53.142 ha. Hence, the status of balance 9.432 ha forest land needs submission.	<p>2. 7.623 Ha area to be diverted from Bina OCP of M/s NCL from the Forest Clearance obtained for 378.935 Ha vide letter no. 8-58/2005-FC dated 13.08.2007. Transfer of the same from Bina OCP to Khadia OCP is in process.</p> <p>3. For remaining 53.142 Ha area, present application has been made.</p>						
xviii.	The user agency is submitting the proposal for diversion of forest land in piecemeal. The reasons for the same needs submission.	<ul style="list-style-type: none"> Forest Clearance of 180 Ha was obtained for the purpose of expansion of Khadia Opencast project from 4 MTPA to 10 MTPA. The current expansion is being sought for expansion of Khadia OCP to 20 MTPA. Also, as detailed above, out of total 904.765 Ha : <ul style="list-style-type: none"> Forest Clearance has been obtained in Uttar Pradesh state for 664 Ha, in Madhya Pradesh state for 180 Ha & 7.623 Ha is being transferred from Bina OCP and Forest Clearance is being sought for remaining 53.142 Ha forest land. There is no other forest land remaining other than this 53.142 Ha forest land, which requires forestry clearance. 						
xix.	The area proposed for diversion is having high biological richness as per DSS analysis. The justification for proposing such biodiversity rich area for mining shall be submitted. Also the State Govt. shall submit the status of unbroken area available in the vicinity of the proposed diversion and within the mining lease area.	<ul style="list-style-type: none"> The proposed forest land to be diverted is coal bearing area and as per approved Mining Plan, additional around 35.46 Million Tonne of coal will be extracted from proposed expansion. Coal mining is site specific activity and the land is notified under Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957. There is no unbroken land available in the vicinity of Khadia OCP as the Khadia OCP is surrounded by Dudhichua OCP in West direction, Krishnashila OCP in East direction and Bina Extension OCP in North East direction. As on 01.07.2024, around 110.63 Ha (including UP and MP state) unbroken coal bearing land is available within mine lease area, details of which as below. <table border="1"> <tr> <td>Type of land</td><td>With MP state in Mine lease area (in Ha)</td><td>With UP state in Mine lease area (in Ha)</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td></tr> </table>	Type of land	With MP state in Mine lease area (in Ha)	With UP state in Mine lease area (in Ha)			
Type of land	With MP state in Mine lease area (in Ha)	With UP state in Mine lease area (in Ha)						

R
22/

Sl. No.	Query	Reply		
		Forest land	49.17	41.88
		Non Forest land	0	19.58
		Total	49.17	61.46

6/7/9/10/24

General Manager
Khadia Area, NCL

[Signature]

Northern Coalfields Limited
Khadia Area

STATUS OF THE CONDITIONS AS MENTIONED IN THE LETTER NO. 8-85/2005-FC DATED 14.09.2010 FROM MOEF, NEW DELHI PERTAINING TO TRANSFER OF 180 HA FOREST LAND (IN M.P.) TO KHADIA PROJECT.

S.N.	CONDITIONS	STATUS OF COMPLIANCE
1	General description regarding stage-1 approval.	The State Govt. has furnished compliance report and requested the Central Govt. to grant final approval.
2(i)	Legal status of land shall remain unchanged.	Yes. Legal status of land shall remain unchanged.
2(ii)	Compensatory afforestation shall be raised and maintained over degraded forest twice in extent to the forest land diverted (i.e. over $2 \times 180 = 360$ ha).	As demanded by MP forest deptt. Rs 10.80 Cr has been deposited vide SBI Morwa DD No. 210211 dated 06.10.2009 to the office of the DFO, Singrauli for compensatory afforestation on 360 ha degraded forest land.
2(iii)	The user agency shall create, fence and maintain a proper safety zone around the mining area.	For this purpose Rs 2.25 Cr as demanded by MP forest deptt. has been deposited vide SBI Morwa DD no. 210208 dated 06/10/2009 and Rs 18 Lakh vide SBI Morwa DD no. 211008 dated 29/10/2009 respectively to the office of the DFO Singrauli for safety zone around the mining area.
2(iv)	The State Government shall protect and regenerate safety zone area, afforest degraded forest elsewhere one and half time in extent to area of safety zone.	For this purpose Rs 27 lakh as demanded by MP forest deptt. has been deposited vide SBI Morwa DD no. 210210 dated 06/10/2009 to DFO Singrauli.
2(v)	Wherever possible and technically feasible, the user agency shall in consultation with State Forest Department, afforest blanks within the lease area as well as along the roads outside the lease area diverted under this approval at the project cost.	The feasibility study was conducted by MP Forest deptt. and an estimate for Rs 150.59 Lakhs was given to project vide Ma Chi/848 dated 22/03/2012 for road side plantation (both side) from Khadia to Jhingurdah in a distance of 12 Km. accordingly. The amount of Rs 150.59 Lakh has been deposited to DFO, Singrauli by Bank draft no. 269768 dated 17/04/2012 by GM (Planning)/Khadia Project on 18/04/2012.
2(vi)	Following activities shall be undertaken by the user agency at the project cost.	
(a)	a detailed plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.	The 180 Ha forest land in M.P. has been finally handed over to the project on 30.09.2013. The soil erosion is being taken care during progress of mining work in the area through afforestation, gabion wall, retaining wall etc.. Gabion wall/retaining wall are constructed wherever necessary to avoid siltation.

2

(b)	Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.	Massive plantation of selected species as recommended by State Forest Research Institute (SFRI) is being done on Overburden dumps through UP forest department in U.P. state. however dumps have not achieved their final height in M.P. state.
(c)	Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.	Being done every year under monsoon preparation and mine development.
(d)	The area shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28 degree at any given place) are maintained.	Till date, dumping has not started in the 180 Ha forest land. All present dumps are active dumps and advised measures are being taken care to all possible extent. After achieving top profile of the dump, the final reclamation will be done keeping in view the international practices.
(e)	The top soil management plan should be strictly adhered to.	At Khadia OCP, top soil is available in patches. The top soil management is being done as per EMP.
2(vii)	Additional amount of NPV of the diverted additional forest land if any becoming due to after finalization of the same by Hon'ble Supreme Court of India shall be charged by the State Government from the user Agency.	Rs 11.25 Cr as demanded by MP forest deptt. against NPV has deposited vide SBI DD no. 210209 dated 06/10/2009 and Rs 1.8 Lakh against deference of NPV as demanded by MP forest deptt. has been deposited vide Allahabad Bank Shaktinagar DD no. 619375 dated 11/01/2012 to DFO Singrauli. However, Project is committed to pay any demand raised in future in this regard.
2(viii)	The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.	Yes. The forest land is not being used and shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
2(ix)	The detailed assessment of the proposal after 3 years of implementation shall be done by Regional Office at the user agency's cost from a reputed institution.	Agreed. Project is committed to bear cost for any such assessment.
2(x)	Concurrent reclamation with minimum felling of trees shall be done by the user Agency so that impact is minimal.	Concurrent reclamation is a continuous process and is being complied.
2 (xi)	The approval under the Forest (conservation) Act 1980 is subject to the clearance under the Environment (protection) Act 1986.	Agreed. The Environmental clearance for Khadia Expansion Project (15MTY) have been obtained from MOEF New Delhi vide J-11015/255/2006-IA.II(M) Dated -07.02.2024.
2(xii)	The user agency will make arrangement for free supply of Coal or LPG refills to labours and staffs working on the project site so as to avoid any pressure on adjacent forest areas.	Free supply of LPG to the labour and staff is being given. Mine canteens are being run on subsidised cost of food items available for both employees and labours so as to avoid any pressure on adjacent forest areas.
2(xiii)	The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act 1980 will be for 20 years subject to possession of valid lease by user agency under MMRD Act. 1957.	The land has been acquired under Coal Bearing Act. Khadia Project acknowledge the period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act. 1980 as 20 years.

2(xiv)	Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers forward and back bearing and distance from pillars to pillars.	Demarcation of mining lease area has been done through construction of 70 nos RCC pillars under W.O. No. 2020/Kh/C/LOA /Demarcation pillar/ 1761/2012/2141 dated 08.12.2012 .
2(xv)	Mining / reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environment Management Plan /phased programme.	Mining / Reclamation schedule is being implemented as per Environment Management Plan /phased programme.
2(xvi)	The user agency shall take up afforestation and soil moisture conservation works inside the forest area in 100 m radius from the permitted lease area in consultation with the forest deptt. Wherever the forest density is less than 0.4, gap plantation should be taken up.	For work beyond lease area forest deptt. the demand of cost raised by forest deptt. will be paid. The work within the lease area is being done through forest deptt. as per availability of land.
2(xvii)	The user agency shall also take up study on soil erosion / soil flow from the overburden areas with the help of GIS in consultation with forest department.	For this purpose, payment of Rs 10.65 Lakhs has been made vide draft nos. 619592 (Rs 5.0 lakhs) & 619593 (Rs 5.65 lakhs), dated 07/03/2012 in favour of " The Director, SFRI, Jabalpur" and study has been completed.
2(xviii)	The user agency shall take up the desilting of the village tanks within five Km areas from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks whenever required.	Regular cleaning of drain and nallah of nearby villages is being done by Khadia Project.
2(xix)	All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental clearance and rehabilitation of tribal and other forest dwellers shall be complied with.	Agreed. All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental clearance etc. are being complied with.
2(xx)	Any other conditions that State Govt. of Madhya Pradesh or the Chief Conservator of Forest (Central). Ministry of Environment & Forest, Regional Office, Bhopal may impose from time to time in the interest of conservation, protection or development of forests.	Any other conditions that State Govt. of Madhya Pradesh or the Chief Conservator of Forest (Central). Ministry of Environment & Forest, Regional Office, Bhopal may impose, shall be complied.

6/79/07/24

General Manager
Khadia Area

[Signature]

**Northern Coalfields Limited
Khadia Area**

**Cost Benefit Analysis Report for Diversion of 53.142 ha. Forest Land for
Khadia Expansion Opencast Coal Mining Project of
Northern Coalfields Ltd., Singrauli**

INTRODUCTION

Khadia Expansion Opencast Coal Mine of the Northern Coalfields Limited, Singrauli (A subsidiary of Coal India Limited) is operating in Singrauli District of Madhya Pradesh State and Sonebadra District of Uttar Pradesh having production capacity of 15 MTPA. Further 53.142 ha. forest land is required to be diverted for the expansion of project from 15 MTPA to 20 MTPA.

Name of Project	Total Area as per Mine Plan (Ha.)	Forest land already diverted (ha.)	Proposed Forest land to be diverted (ha.)	Non Forest Land involved (ha.)	Life of mine in Yrs.
Khadia Expansion OCP	1697.906	851.623	53.142	793.141	12 yrs. w.e.f 01.04.2023

PURPOSE FOR COST BENEFIT ANALYSIS :

Cost Benefit Analysis report is required for making on line application in Part- 1of FORM-A for diversion of forest land.

Cost Benefit Analysis report as per guidelines given in Annexure-III of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest (Conservation) Amendment Rules 2016, issued by MoEF&CC:

ESTIMATED COST FOR FOREST DIVERSION

SN	Parameters	Guidelines	Calculations	Cost (in Lakhs)
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	Economic value of loss of eco-system services due to diversion of forests shall be net present value (NPV) of the forest land being diverted as Prescribed by Central Government (MoEF&CC)	Net present value (NPV) of the forest land being diverted = 12,28,590/ Ha. (NPV for Class-III Eco class, Dense Forest) X 53.142 Ha. = Rs. 652.897Lakhs	652.897
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder	To be quantified and expressed in monetary terms or 10 % of NPV applicable whichever is maximum.	As per MOEF&CC Circular No. 7-69/2011-FC(PT.) Dated 01 August 2017, 10% of NPV has been taken taken which is	65.289

I 42

			Rs. 65.289 Lakhs (10% of 652.897) (Ref: Table 1 below).	
3	Cost of human resettlement	To be Quantified and expressed in monetary terms as per approved R & R plan.	Actual Cost of human resettlement as per R&R Plan = 169.52 Lakhs + 306.8 Lakhs = 476.32 lakhs (Ref: Table 3 below)	476.32
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, buildings, schools, dispensaries, electric line, railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	To be Quantified and expressed in monetary terms on actual cost basis at the time of diversion.	No public facilities and administrative infrastructure (Roads, buildings, schools, dispensaries, electric line, railways, etc.) are existing on the forest land. Therefore, Loss on the above causes would be NIL	0.00
5	Possession value of forest land diverted	30% of environmental cost (NPV) due to loss of forest or Circle rate of adjoining area in the district should be added as a cost component as Possession value of forest land whichever is maximum.	Collector rate of adjoining area - Rs. 13.80 lakhs/Ha. = 53.142 ha. x Rs. 13.80 lakhs = Rs. 733.359 lakhs OR 30% NPV of Forest land = Rs. 652.897 x 0.3= Rs. 195.869 Lakhs whichever is higher ie; Rs. 733.359 Lakhs	733.359
6	Cost of suffering to oustees	The social cost of rehabilitation of oustees (in addition to the cost likely to be incurred in providing residence, occupation and social services as per R & R plan) be worked out as 1.5 times of what oustees should have earned in two years had be not been shifted.	Cost of suffering of oustees : No. of Ousteas = No. of PAFs = 811 No. of Days Worked per year = 300 Days (Assumed) Minimum wages of unskilled labour = Rs. 477/manday Thus, Cost of Suffering of oustees = (1.5 times of earning of 2 years taken as per guidelines) 811 X 300 X 522 X 2 X 1.5/100000 = Rs. 3481.623 Lakhs (Ref. Table 6 (6) below)	3810.078
7	Habitat Fragmentation cost	While the relationship between Fragmentation and forest goods and services is complex, for the sake of simplicity the cost due to	50 % of NPV of forest land = Rs. 12,28,590 x 53.142 x 50% = Rs. 326.448 lakhs	326.448

3 42

		fragmentation has been pegged at 50% of NPV applicable as a thumb rule.		
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost	The actual cost of Compensatory afforestation and soil & moisture conservation and its maintenance in future at present discounted value.	The calculated cost of Compensatory afforestation and soil & moisture conservation = @6 lakhs/ha. (assumed) for 53.142 = 6 x 53.142 x 2 = Rs. 318.852 lakhs.	318.852
Total cost of forest diversion (in lakhs)				6383.243

ESTIMATED BENEFITS FOR FOREST DIVERSION

SN	Parameters	Guidelines	Calculations	Benefits (in Lakhs)
1	Increase in productively attribute to the specific project	To Be quantified & expressed in monetary terms avoiding double counting.	35.46 MT (balance coal reserve) X Rs. 539.78 profit/te) X 10 = Rs. 191405.98 Lakhs	191405.98
2	Benefits to economy due to specific project	The incremental economic benefit in monetary terms due to the activities attributed to the specific project.	As calculated in Table 7 (2) below	283717.97
3	No. of population benefited due to specific project	As per detailed project Report	As calculated in Table 7 (3) below	12800 Nos.
4	Economic benefits due to direct and indirect employment due to project	As per detailed Project Report	As calculated in Table 7 (4) below	49421.96
5	Economic benefits due to compensatory afforestation	Benefits from such compensatory forestation accruing over next 50 years monetized and discounted to the present value should be included as benefits of compensatory afforestation.	As calculated in Table 7 (5) below	143.91
TOTAL (1+2+4+5)				524689.82

Cost benefit ratio: 524689.82/6383.243= 82.19

[Handwritten signature]

The nature of forest land, for which application for diversion of forest land is applied for Khadia OCP (53.142 Ha) falls in Class III Dense Forest (DF). The rate of NPV is Rs. 12,28,590 per ha.

Current NPV Rates –			
(Rs. / Ha)			
Eco- Value Class	VDF(very dense forest)	DF(dense forest)	OF(open forest)
Class III Forest	1357110	12,28,590	957780

Table 1 : Calculation of NPV in respect to Khadia Expansion OCP (Rate of NPV Rs. 12,28,590 per Ha. for Class III Dense Forest)	
Description	Amount in Lakhs
Total NPV for (53.142 Ha. forest land - Class III Dense Forest)	652.897
10% NPV Value	65.289
30% NPV Value	195.869
50% NPV Value	326.448

Table- 2 : Possession Value of Forest Land Diverted

CIRCLE RATE OF LAND

Type of Land nearby Forest Area	Avg. circle rate in Lakhs/Acre	Total Area in Ha.	Rate per Ha. (lakhs)	Cost of land in (Lakhs)
	a	b	c	d= b x c
Agricultural	5.584	53.142	13.80	733.359

REHABILITATION COST:

Table 3: Compensation for Land as per R&R Policy	
Description	Amount in Lakhs
Monetary compensation paid for land, house, tree, well etc.	169.52
Cost of rehabilitation in form of land, house etc.	306.8
*Subsistence allowance to each affected family @ 25 days Minimum Agricultural Wages per month for one year.	Not applicable for open cast mine
Total	476.32

Table 4 (a) : Royalty on Coal			
S.N.	Royalty	Rate	Amount in lakhs
1	Basic royalty	14% of sale price= 0.14 x 1204.73 (Rs./te) x 35.46 (MT) x 10 = 59807.62 lakhs	59807.62

[Handwritten signature]

2	District Mining Fund	30% of royalty = $0.3 \times \text{royalty i.e } 0.3 \times \text{Rs. } 59807.62 \text{ lakhs} = \text{Rs. } 17942.28 \text{ lakhs}$	17942.28
3	National Mineral fund	2% of royalty = $0.02 \times \text{Royalty i.e } 0.02 \times 59807.62 \text{ lakhs} = \text{Rs. } 1196.15 \text{ lakhs}$	1196.15

Table 4 (b): Levy and collection of Cess

Rate of Coal Cess	Amount in lakhs
GST @ 5% of sell price	$\text{Rs. } 1204.73 (\text{Rs./te}) \times 35.46 \text{ MT} \times .05 \times 10 = 21359.86 \text{ lakhs}$
MP Gramin Avsanrachna Tatha Sarak Vikas Adhiniyam (MPGSTVA) Cess @ 5%	$\text{Rs. } 1204.73 (\text{Rs./te}) \times 35.46 \text{ MT} \times .05 \times 10 = 21359.86 \text{ lakhs}$
GST Compensation Cess - @Rs 400 per tonne	$\text{Rs. } 400 \times 35.46 \text{ MT} \times 10 = \text{Rs. } 141840 \text{ lakhs}$
Transit fees @ Rs. 57/tonne for 35.46 MT	$\text{Rs. } 57 \times 35.46 \text{ MT} \times 10 = \text{Rs. } 20212.2 \text{ lakhs}$

OTHER DETAILS

Table 5 : Other Details		
1.	Manpower as per EPR/ Mine Plan	1600
2.	Cost of Production in Rs. / te	Rs. 664.95/te,
3.	Extractable Reserves due to proposed forest land	35.46 MT
4.	Life of the mine-	12 Yrs. W.e.f. 01.04.2023
5.	Grade of coal	G8-G9, Avg.- G9
6.	Wage cost/te as per PR	Rs. 131.59/tonne
7.	Capital Investment as per PR	Additional 491.67 crore
8.	Wt. Avg. Sell price of coal per tone	Rs. 1204.73/tonne
9	Tenancy land	Nil
10	Minimum Labour wages-Unskilled labour	Rs. 522/day (As on 01.04.2024)

Calculation as per guidelines given in Annexure-III of Handbook of Forest(Conservation) Act, 1980 and Forest (Conservation) Amendmend Rules 2016, issued by MoEF&CC.

Table - 6. Estimation of cost of forest diversion

1. Ecosystem services losses due to proposed forest diversion

Economic value of loss of ecosystem services due to diversion of forest = Net present value (NPV) of the forest land being diverted = Rs. 652.897 Lakhs (Ref: Table 1 above)

[Handwritten signature]

2. **Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder** = As per MOEF&CC Circular No. 7-69/2011-FC(PT.) Dated, 01 August, 2017, 10% of NPV is taken for fresh lease which is Rs. 65.289 Lakhs (Ref: Table 1 above).

3. **Cost of human resettlement**

Cost of human resettlement as per R&R Plan = Rs. 169.52 lakhs + Rs. 306.8 lakhs = 476.32 lakhs (Ref. Table 3 above)

4. **Loss of public facilities and administrative infrastructure**(Roads, buildings, schools, dispensaries, electric line, railways, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project – NIL.

5. **Circle rate/Collector rate of adjoining area or Possession value of forest land diverted**

Collector rate of adjoining area = Rs. 13.80 lakhs/Ha.

For 53.142 ha. = Rs. 13.80 lakhs x 53.142 = Rs. 733.359 lakhs

OR

30% NPV of Forest land = Rs. 195.869 Lakhs (Ref: Table 1),
whichever is higher means Rs. 733.359 Lakhs

6. **Cost of suffering of oustees :**

No. of Outsees = No. of PAFs = 811

No. of Days Worked per year = 300 Days (Assumed)

Minimum wages of unskilled labour= Rs.522.00/day

Thus Cost of Suffering of oustees = (1.5 times of earning of 2 years taken as per guidelines)

811 X 300 X 522 X 2 X 1.5/100000 = **Rs. 3810.078 Lakhs**

7. **Habitat Fragmentation cost:**

Cost due to fragmentation has been pegged at 50% of NPV applicable as a thumb rule (Ref Circular MoEF)

50 % NPV = **Rs. 326.448 lakhs** (Ref: Table 1 above)

8. **Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost= @6 lakhs/ha. for 53.142 = 6 x 53.142 = Rs 318.852 lakhs.**

Table -7 .

Estimating benefits of forest – diversion in CBA

1. **Increase in productively attribute to the specific project- productively attribute**

P = 35.46 MT (additional coal reserve) X Rs. 539.78 profit/te X 10 = **Rs. 191405.98 Lakhs**

2. **Benefits to economy due to specific project:**

Different Benefits	In Lakhs	Ref. Table above
Basic Royalty	59807.62	Table 4(a) above
District Mineral Fund	17942.28	Table 4 (a) above
National Mineral Fund	1196.15	Table 4 (a) above
GST 5%	21359.86	Table 4 (b) above

8/5/21

MP Gramin Avsanrachna Tatha Sarak Vikas Adhiniyam (MPGSTVA) Cess	21359.86	Table 4 (b) above
GST Compensation Cess @ Rs. 400/Ton	141840.00	Table 4 (b) above
Transit Fee @ Rs. 57/ton on 35.46 MT	20212.2	Table 4 (b) above
Total	283717.97	

3. No of population benefitted due to specific project:

Direct employment = 1600

Indirect Employment = Direct Employment x 2 = 3200

Considering avg. family size 4, then no. of Population will be benefitted = 3200 x 4 =
12800 nos.


4. Economic benefits due to direct and indirect employment due to project:

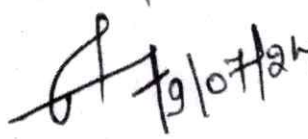
Economic benefits	Rs. In Lakhs
Direct Employment Benefit (Coal Reserve x wage cost/te X income tax (20%))	Rs. 35.46 (MT) x 131.59 (Rs./te) x 0.20 x 10 = Rs. 9332.36 lakhs
Indirect employment benefit = (Total manpower = 1600) x 2 x 12 (life of mine) x 200 (Avg. working day/yr.) x Min.wages/day (Rs. 522/manday)	Rs. 1600 x 2 x 12 x 200 x 522 /100000 = Rs. 40089.60 lakhs
Total	49421.96 lakhs

5. Economic benefits due to compensatory afforestation:

Economic benefits	In Rs. Lakh
Due to compensatory afforestation (CA land X Difference of NPV for class III (Dense forest - open forest) = (53.142 ha X (12,28,590-957780) /100000 = Rs. 143.91 lakhs	143.91


Staff Officer (Mining)
Khadia Area


Nodal Officer (Env)
Khadia Area


Area General Manager
Khadia Area

NO.8-298/87-FC

To

The Secretary (Forest),
Govt. of Uttar Pradesh,
Lucknow.

Sub: Transfer of 1305 ha. of forest land to Northern Coal Field Ltd. for
Dudichuha & Kharla Coal Projects, Mirzapur (Sonbhadra) district.

Sir,

I am directed to refer to your letter NO.4849/14-3-929/87 dated 3.10.87 on the above subject seeking prior approval of the Central Govt. in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 and to say that the proposal has been examined by the Advisory Committee constituted by the Central Govt. under Section 3 of the aforesaid Act.

After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the above mentioned Advisory Committee, the Central Govt. hereby conveys its approval under Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for transfer of 1305 ha. of forest land to Northern Coal Field Ltd. for Dudichuha & Kharla Coal Projects, Mirzapur (Sonbhadra) district subject to following conditions:

1. The legal status of the land will remain unchanged.

2. The mined over area will be reclaimed after mining is over at the cost of the project as per the scheme submitted by project authority.

3. The compensatory afforestation will be raised over 1565.59 ha. of non-forest area as identified in Kanpur, Pratapgarh and Sultanpur districts under Social Forestry Programme at the cost of the project. The area so identified will be notified as protected forest before handing over the area being diverted by this order. 4. Rehabilitation of the oustees families will be done as per the scheme submitted by the State Govt. at the cost of the project. 5. In order that labour and staff while working on the project in the forest area may not cause destruction to the forest area for meeting their fuelwood needs, the user agency will establish fuelwood depot and will provide the fuelwood to them free of cost.

be stored in

6 NO explosives should be allowed to the forest area.

7. The condition/safe guard imposed by the Department of Environment of this Ministry, while clearing the project, are to be strictly followed.

8. The details of forest area to be diverted for various works of the projects is as follow:

	Kharla Project	Dudichuha Project
a) Mining	703.0	352.0 ha.
b) Storing of minerals	NIL	5.0 ha.
c) Dumping of overbenden	47.0	127.0 ha.
d) Storing tools/machines	NIL	NIL

...2/-

दूरभाष 1
Telephone :

तार :

Telegram : PARYAVARAN,
NEW DELHI

पर्यावरण भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स,
PARYAVARAN BHAWAN, C.G.O. COMPLEX,
लोदी रोड, नई दिल्ली-110003
LODI ROAD, NEW DELHI-110003

30th July, 1990 .

Annexure
86-1

Khadija ProjectDudhichuha Project

- a) Construction of building,
Power station, Workshop etc.
b) Township/Colony
c) Construction of road/
roadway/Railway line/Power line
d) Environment
Total

NIL
NIL
NIL
NIL
750.0

15.0 ha.
NIL
39.0 ha.
17.0 ha.
555.0 ha.

Yours faithfully,

(Khazan Singh)
Asstt. Inspector General of Forest.

Copy to:

1. PCCF, Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. CCF (Central) Regional Office, Lucknow.
3. Nodal officer (Sh. K. Prasad) 17-Rana Pratap Marg, Lucknow.
4. Regional Office (Hq)
5. Guard file.

(Khazan Singh)
A.

File No. 8-85/2005-FC
Government of India
Ministry of Environment and Forests
(F.C. Division)

Paryavaran Bhawan,
CGO Complex, Lodhi Road,
New Delhi - 110 003.
Dated 14th September, 2010

To

**The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.**

Sub: Diversion of 180.00 ha of forest land for Khadia Project of Northern Coalfields Limited (NCL) in Sidhi District of Madhya Pradesh.

Sir,

I am directed to refer to Government of Madhya Pradesh's letter No. F-1/371/05/2005/10-11/2537 dated 29.09.2005 on the above mentioned subject wherein prior approval of the Central Government for diversion of 180.00 ha of forest land for Khadia Project of Northern Coalfields Limited (NCL) in Sidhi District of Madhya Pradesh, was sought, in accordance with Section 2 of the Forest (Conservation) Act, 1980. After careful consideration of the proposal by the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under Section-3 of the said Act, in-principle/stage-I approval for the said diversion was granted vide this Ministry's letter of even number dated 08.06.2009 read with corrigendum dated 18.06.2009, subject to fulfillment of certain conditions. The State Government has furnished compliance report in respect of the conditions stipulated in the in-principle approval and has requested the Central Government to grant final approval.

2. In this connection, I am directed to say that on the basis of the compliance report furnished by the State Government vide letter No. F-1/371/05/10-11/91 dated 12.01.2010 and No. F-1/371/05/10-11/1985 dated 02.06.2010, final/stage-II approval of the Central Government is hereby granted under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980 for diversion of 180.00 ha of forest land for Khadia Project of Northern Coalfields Limited (NCL) in Sidhi District of Madhya Pradesh, subject to fulfillment of the following conditions:-

- (i) Legal status of forest land shall remain unchanged.
- (ii) Compensatory afforestation shall be raised and maintained over degraded forest twice in extent to the forest land diverted (i.e. over $2 \times 180 = 360$ ha.).
- (iii) The User Agency shall create, fence and maintain a proper safety zone around the mining area.
- (iv) The State Government shall protect and regenerate safety zone area, and afforest degraded forest elsewhere, one and half time in extent to area of the safety zone.
- (v) Wherever possible and technically feasible, the User Agency shall in consultation with the State Forest Department, afforest blanks within the lease area, as well as

o/c

4/10/2010

along the roads outside the lease area diverted under this approval, at the project cost.

- (vi) Following activities shall be undertaken by the User Agency at the project cost:
- (a) A detailed plan containing appropriate mitigative measures to minimize soil erosion and choking of streams shall be prepared and implemented.
 - (b) Planting of adequate drought hardy plant species and sowing of seeds to arrest soil erosion.
 - (c) Construction of check dams, retention / toe walls to arrest sliding down of the excavated material along the contour.
 - (d) The areas shall be reclaimed keeping in view the international practice of stabilizing the dumps by grading / benching so that angles of repose (normally less than 28° at any given place) are maintained.
 - (e) The top soil management plan should be strictly adhered to.
- (vii) Additional amount of the NPV of the diverted additional forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India, shall be charged by the State Government from the User Agency.
- (viii) The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
- (ix) The detailed assessment of the proposal after 3 years of implementation shall be done by Regional Office at the User Agency's cost from a reputed institution.
- (x) Concurrent reclamation with minimum felling of trees shall be done by the User Agency so that impact is minimal.
- (xi) The approval under the Forest (Conservation) Act, 1980 is subject to the clearance under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (xii) The user agency will make arrangement for free supply of coal or LPG refills to labourers and staff working on the project site so as to avoid any pressure on the adjacent forest areas.
- (xiii) The period of permission for lease under the Forest (Conservation) Act, 1980 will be for 20 years subject to possession of valid lease by User Agency under the MMDR Act, 1957.
- (xiv) Demarcation of mining lease area will be done on the ground at project cost using four feet high reinforced cement concrete pillars with serial numbers, forward and back bearings and distance from pillar to pillar.
- (xv) Mining/reclamation schedule shall be implemented by the user agency at their cost as per Environmental Management Plan / Phased programme.
- (xvi) The User Agency shall take up afforestation and soil moisture conservations works inside the forest area in 100 m. radius from the permitted lease area in consultation with the forest department. Wherever the forest density is less than 0.4, gap plantation should be taken-up.

14/09/2014

- (xvii) The User Agency shall also take up study on soil erosion / soil flow from the over-burden areas with the help of GIS in consultation with the forest department.
- (xviii) The User Agency shall take up the de-silting of the village tanks within five km area from the mine lease boundary so as to mitigate the impact of siltation of such tanks whenever required.
- (xix) All other conditions under different rules, regulations and guidelines including environmental clearance and rehabilitation of tribal and other forest dweller shall be complied with.
- (xx) Any other condition that the State Government of Madhya Pradesh or the Chief Conservator of Forests (Central), Ministry of Environment & Forests, Regional Office, Bhopal may impose from time to time in the interest of conservation, protection or development of forests.

Yours faithfully,

14/09/2010

(H. C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
2. The Nodal Officer, Forest Department, Government of Madhya Pradesh, Bhopal.
3. The CCF(Central), Regional Office, Bhopal.
4. User Agency.
5. Monitoring Cell, FC Division, MoEF, New Delhi.
6. Guard File.

14/09/2010

(H. C. Chaudhary)

Assistant Inspector General of Forests

*Received
D-3-1711
Adm. Cell
New Delhi*

*issued
16/9/2010*

F. No. 8 - 58/2005-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

Paryavaran Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003

Dated: 13th August, 2007

To

The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 378.935 ha. of forest land for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F-1 / 368 / 05 / 10-11 / 1345 dated 31.05.2005 on the above mentioned subject, wherein the above proposal for diversion of **378.935 ha.** of forest land for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh was submitted seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government granted in-principle approval to the said proposal under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, on 18.07.2006. The request of the User Agency, that the Condition No 1 of the order dated 18.07.2006 may be changed suitably incorporating therein raising Compensatory Afforestation over double degraded forest land as is applicable to Central Government Public Undertaking, was placed before the Forest Advisory Committee in its meeting held on 27.09.2006. The Forest Advisory Committee recommended to change the Condition No. 1 of the order dated 18.07.2006 as follows:- **"The Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over the degraded forest land double in extent to the area broken after 1980, at the cost of the User Agency."**

3. A compliance report has been received from the Nodal Officer (FC), Madhya Pradesh, vide letter No. F-1/368/05/10-11/460 dated 21.02.2007. After considering the proposal and compliance of the stipulated conditions by the State Government, the Central Government hereby grants approval, under the Forest (Conservation) Act, 1980, for **diversion of 378.935 ha. of forest land** for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh, subject to fulfilment of following conditions :-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. The Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over degraded forest land double in extent to the area broken after 1980, by the User Agency at the Project Cost.

3. The State Government shall charge the Net Present Value of the forest area diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002 and 01.08.2003 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 in this regard.
4. The State Government shall deposit NPV and all other funds with the Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in Account No. CA 1579 of Corporation Bank, Block-11, Ground Floor, CGO Complex, Phase-1, Lodhi Road, New Delhi-110003.
5. Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
6. The User Agency shall create, fence and maintain a proper safety zone around the mining area. The User Agency shall deposit funds with the Forest Department for the creation, protection and regeneration of the safety zone area, and also shall bear the cost of afforestation over one and a half time of the safety zone area in degraded forest elsewhere.
7. Phased reclamation of the mine shall be carried out by the User Agency as per the approved Reclamation Plan at the Project Cost.
8. Rehabilitation and resettlement of the displaced persons shall be carried out by the User Agency as per the R & R plan submitted for the purpose.
9. Demarcation of the area shall be done on ground at the project cost using four feet high RCC pillars with serial numbers, forward and back bearings and distances from pillar to pillar.
10. Trees shall be felled only when it becomes necessary and that should be done under strict supervision of the State Forest Department.
11. No labor camps shall be established on the forest land.
12. Sufficient firewood shall be provided by the User Agency to the laborers at the project cost after purchase from the State Forest Department/Forest Development Corporation.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
14. The User Agency shall ensure that there should be no damage to the wildlife in the area.
15. All other standard conditions stipulated for Mining Projects shall be complied with by the User Agency.

Yours faithfully,

(A.K. Joshi)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow
4. User Agency
5. RO (HQ), New Delhi/ Monitoring Cell / FC Div.
6. Guard file.

(A.K. Joshi)

Assistant Inspector General of Forests

Annexure D

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
खडिया परियोजना
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
Khadia Project
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

थाना- शक्तिनगर, जनपद-सोनभद्र (उ. प्र.), पिन - 231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonebhadra (U.P.) Pin- 231222
Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: cgm.khd@gmail.com, website : www.nclcil.in

Ref: NCL/KHD/GM/Min/Env/FC 53.142/2024-25/ 4246

Date: 20/4/24

To,
Executive Engineer,
Water Resource Department,
Sl. No. -02,
Singrauli, Madhya Pradesh

Subject:- Comments on proposed measures and impact of the project on hydrological regime.

Dear Sir,

Khadia Expansion Opencast Project of M/s Northern Coalfields Limited has applied for forestry clearance of 53.142 Ha forest land in Singrauli District of Madhya Pradesh. During the processing of the said application, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), New Delhi has raised a query as detailed below.

"As per the Mining plan, it has been reported that numerous seasonal nallas flowing through this area and meet the master drain the Rihand dam (Govind Ballabh Pant Sagar) which is located south of this area. Tippa Jharia nala drains the Khadia (Expansion) OCP area in north and Ballia nalla drains this OCP in south and meet the Gobind Ballabh Pant Sagar. Therefore, comments of the water resource department on the proposed measures and impact of the project on the hydrological regime are required to be submitted."

In compliance of the above, a plan for conservation and protection of seasonal nallahs flowing through the leasehold area of Khadia Expansion Opencast Project, NCL is enclosed herewith.

It is requested to kindly give your comment on the proposed measures and impact of the project on the hydrological regime.

Encl.:- As above.



Yours faithfully,

20/04/24
General Manager
Khadia Area, NCL

**Northern Coalfields Limited
Khadia OCP**

**Plan for conservation and protection of seasonal nallahs flowing through
the leasehold area of Khadia Expansion Opencast Project, NCL (1697.906
Ha Area).**

1. Tippa Jharia:-

Tippa Jharia does not flow from the leasehold boundary of Khadia OCP (1697.906 Ha). However, some of the drainage flowing from leasehold boundary in monsoon season and carrying storm water meets Tippa Jharia in the North.

Details and plan of conservation and protection of these drainage pattern (total 03) are as detailed below.

a) Seasonal Drain-1:

Brief Details of Seasonal Drain			
Sl. No.	Particulars	Details	
1	Type of Seasonal Drain	Ephemeral (Seasonal)	
2	Location within mine boundary	Start	End
	(i) Latitude	24°9'1.5084"	24°9'8.7624"
	(ii) Longitude	82°43'1.33"	82°43'0.653"
3	Length of Seasonal Drain	Approx 380 m within mine lease area.	
4	Direction of flow	A ridge / highest point lies in the drain within mine leasehold area. From that point, a portion of the water flows towards South west direction and another portion flow towards North Direction.	
5	Discharge	Dry throughout the year but it carries some discharge in the monsoon season.	

Plan for Conservation and Protection:-

The highest point of Seasonal Drain-1 is within the mine leasehold boundary, as shown with the contour in map enclosed at Annexure-1, The drain is generally dry except in monsoon season and the downward (southward) flow of the drain is collected within the sump created within mine premises of Khadia and Dudhichua. The outward (Northward) flow of this drainage meets Tippa Jharia Drain in North which ultimately discharges into Rihand Reservoir, therefore when the mine will progress in North direction, the seasonal drain- 1 will be cut off part by part, without interrupting the course of seasonal drainage. A surface plan of the mine lease with existing drain is enclosed herewith as Annexure-1. Howsoever, for the protection of existing drain, gabion walls will be constructed at the time of mining in the vicinity of this drain. Since it is a very small drainage and Ephemeral in nature, river training measures are not required. Since the bed and side slopes of Seasonal Drain-1 is made of sandstone, the stone pitching work is not required to prevent erosion.

[Signature]
Dr. M. R. (S. S.)
Khadia

[Signature]
19/4/14

[Signature]

Waste Management Plan of the Seasonal Drainage-1:

Khadia OCP is an existing mine with OB removal started from 1981-82. The major waste generated from mining activities is overburden. The overburden is completely being backfilled in the mine voids created due to excavation of coal. Also the Overburden dumps are being technically and biologically reclaimed. The overburden waste is not being dumped in or around the existing season Seasonal Drains.

Since the said drain will be intersected during the course of the mining, elevation of which will always be more than mine pit, there will be no scope of discharge of mine water / effluent in to drainage. Also, every year monsoon action plan is prepared at Khadia OCP and the run off of the mine area are led to Mine Sumps / Sedimentation ponds constructed within the mine area.

This drain lies in part of mine area which is in MP state, where no handling of hazardous / chemical substances takes place. Hence, there will be no chance of mixing of hazardous / chemical substances in surface run off discharging in the seasonal drain.

b) Seasonal Drain-2:

Brief Details of Seasonal drain

Sl. No.	Particulars	Details	
1	Type of Seasonal Drain	Ephemeral Seasonal Drain (Seasonal)	
2	Location within mine boundary	Starting Point	End Point
	(i) Latitude	24°8'44.6424"	24°9'9.7308"
	(ii) Longitude	82°43'17.958"	82°43'12.961"
3	Length of Seasonal Drain	Approx 840 m.	
4	Direction of flow	Northward	
5	Discharge	Dry throughout the year but it carries some discharge in the monsoon season.	

Plan for Conservation and Protection:-

Seasonal Drain-2 flow from South to North and meets Tippa Jharia Nalla which ultimately discharges into Rihand Reservoir, therefore when the mine will progress in North Direction, the Seasonal Drain- 2 will be cut off part by part, without interrupting the course of seasonal drainage. Also the Drain, as shown in the enclosed map, originates inside the mine lease area therefore no diversion of the same is required. A surface plan of the mine lease with existing Seasonal Drain is enclosed herewith as Annexure-1. Howsoever, for the protection of existing Seasonal Drain, gabion walls will be constructed at the time of mining in the vicinity of the Seasonal Drain. Since it is a very small Seasonal Drain and ephemeral in nature, river training measures are not required. Since the bed and side slopes of Nalla-1 is made of Sandstone, the stone pitching work is not required to prevent erosion.

Waste Management Plan of the Seasonal Drain-2:-

Khadia OCP is an existing mine with OB removal started from 1981-82. The major waste generated from mining activities is overburden. The overburden is completely being backfilled in the mine voids created due to excavation of coal. Also the Overburden dumps

E. M. Singh
Khadia

SKV

T. S. Singh

are being technically and biologically reclaimed. The overburden waste is not being dumped in or around the existing season Seasonal Drains.

Since the said Seasonal Drain will be intersected during the course of the mining, elevation of which will always be more than the depth of quarry of the mine, there will be no scope of discharge of mine water / effluent in the Seasonal Drain. Also, every year monsoon action plan is prepared & enforced at Khadia OCP and the run off of the mine are led to mine sumps / sedimentation ponds.

This Seasonal Drain lies in part of mine area which is in MP state where no handling of hazardous / chemical substances takes place, hence there will be no chance of mixing of hazardous / chemical substances in surface run discharging in the Seasonal Drain.

c) Seasonal Drain-3:

Brief Details of Seasonal Drain

Sl. No.	Particulars	Details	
1	Type of Seasonal Drain	Ephemeral Seasonal Drain (Seasonal)	
2	Location within mine boundary	Starting point	End Point
	(i) Latitude	24°8'28.9536"	24°9'3.2112"
	(ii) Longitude	82°43'28.42"	82°43'37.038"
3	Length of Seasonal Drain	Approx 1245 m.	
4	Direction of flow	Northward	
5	Discharge	Dry throughout the year but it carries some discharge in the monsoon season.	

Plan for Conservation and Protection:-

Seasonal Drain-3 flow from South to North and meets Tippa Jharia Nalla in North which ultimately discharges into Rihand Reservoir, therefore when the mine will progress in North direction, the Seasonal Drain- 1 will be cut off part by part, , without interrupting the course of seasonal drainage. Also the Drain, as shown in the enclosed map, originates inside the mine lease area therefore no diversion of the same is required. A surface plan of the mine lease with existing Seasonal Drain is enclosed herewith as Annexure-1. Howsoever, for the protection of existing Seasonal Drain, gabion walls will be constructed at the time of mining in the vicinity of the Seasonal Drain. Since it is a very small Seasonal Drain and Ephemeral in nature, river training measures are not required. Since the bed and side slopes of Drain-1 is made of sandstone, the stone pitching work is not required to prevent erosion.

Waste Management Plan of the Seasonal Drain-3:

Khadia OCP is an existing mine with OB removal started from 1981-82. The major waste generated from mining activities is overburden. The overburden is completely being backfilled in the mine voids created due to excavation of coal. Also the Overburden dumps are being technically and biologically reclaimed. The overburden waste is not being dumped in or around the existing season Seasonal Drains.

Since the said Seasonal Drain will be intersected during the course of the mining, elevation of which will always be more than mine pit, there will be no scope of discharge of mine water / effluent in to Seasonal Drain. Also, every year monsoon action plan is prepared at

[Signature]
Manager (G)
Khadia

[Signature]

[Signature]

Khadia OCP and the run off of the mine area are led to Mine Sumps / Sedimentation ponds constructed within the mine area.

This Seasonal Drain lies in part of mine area, where no handling of hazardous / chemical substances takes place. Hence, there will be no chance of mixing of hazardous / chemical substances in surface run off discharging in the Seasonal Drain.

2. Balia Nallah:-

Brief Details of Nallah

Sl. No.	Particulars	Details	
1	Type of Nallah	Ephemeral nallah (Seasonal)	
2	Location within mine boundary	Starting Point	Ending Point
	(i) Latitude	24°7'28.7076"	24°7'7.6692"
	(ii) Longitude	82°39'54.367"	82°40'38.579"
3	Length of Nallah	Does not enter mine premises.	
4	Direction of flow	Towards South East	
5	Discharge	Dry throughout the year but it carries some discharge in the monsoon season.	

Plan for Conservation and Protection:

Balia-Nallah flows from North West to South East along the Khadia leasehold boundary, which ultimately discharges into Rihand Reservoir. Balia nalla does not enter in leasehold area as shown in the map enclosed at Annexure 1. Also any stream of Balia Nallah does not flow through the mine boundary except storm water run-off of the residential township area of Khadia OCP. Also the leasehold boundary of Khadia OCP towards Balia nallah is a close boundary with brick masonry walls.

Waste Management Plan of the Balia Nallah:

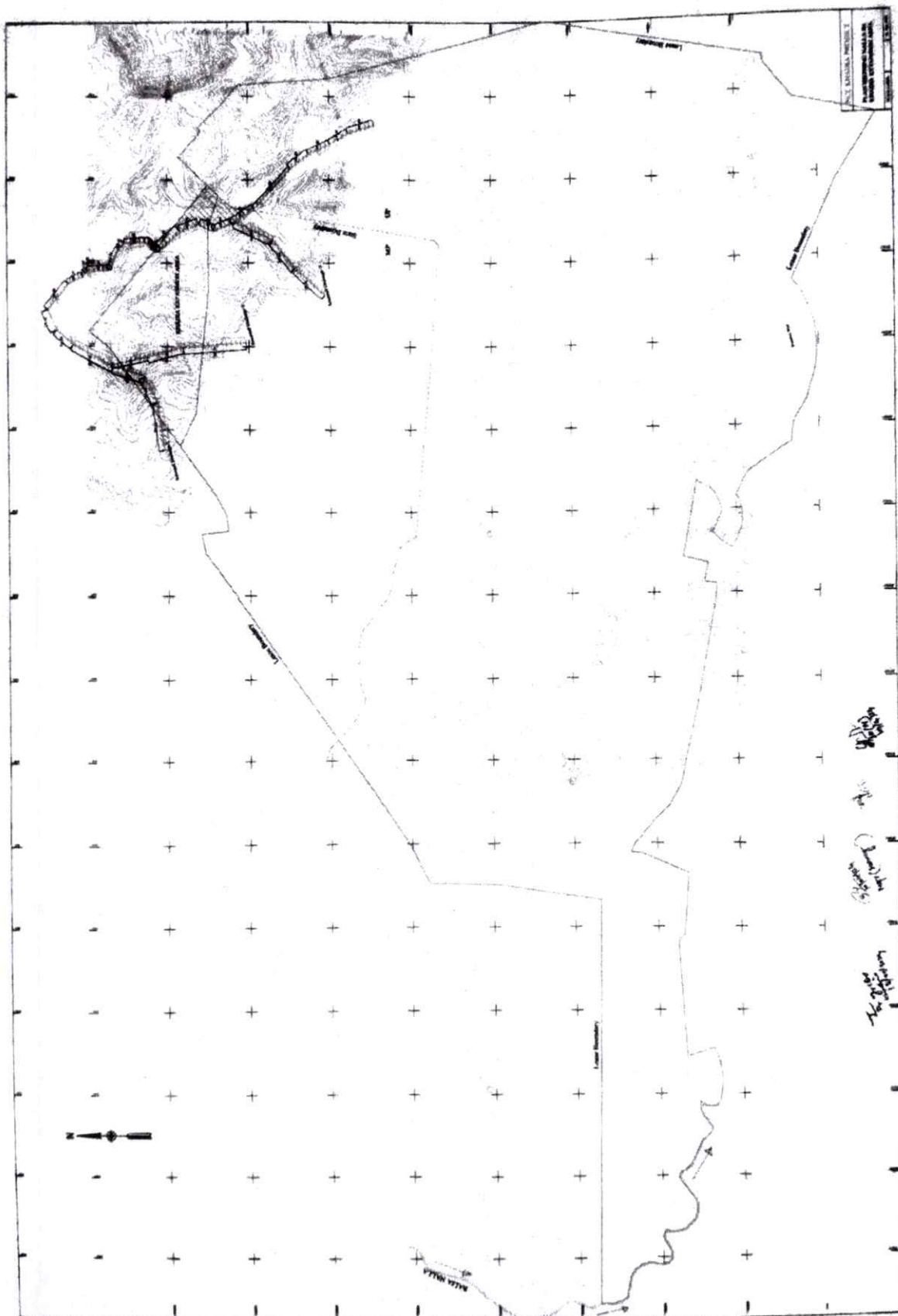
Khadia OCP is an existing mine with OB removal started from 1981-82. The major waste generated from mining activities is overburden. The overburden is completely being backfilled in the mine voids created due to excavation of coal. Also the Overburden dumps are being technically and biologically reclaimed. The overburden waste is not being dumped in or around the existing season nallahs.

Since the Balia Nallah is flowing near to only residential township area of Khadia OCP and active mining operations are being carried out at considerable distance, there is no chance of discharge of effluent from Khadia OCP into Balia Nallah. The effluent generated from residential township area is being treated in Sewage Treatment Plant (1.5 MLD capacity) and the treated water is being reused for horticulture purposes in Nandan Kanan Park, Miyawaki Plantation site, parks built up for various purposes located within the residential township of Khadia OCP etc.

*I
S. Singh
Khadia*

gs

SA



Map of [Illegible]
[Illegible]
[Illegible]

कार्यालय कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरीली (म0प्र0)पत्र क्र0 **621** तकनीकी / 2024
प्रति,

(Email ID - eewrdsingrauli@gmail.com)

सिंगरीली दिनांक **27/4/2024****जनरल मैनेजर
खड़िया एरिया एन.सी.एल.
जिला-सिंगरीली (म0प्र0)****विषय:-** एन.सी.एल. खड़िया क्षेत्र के वनभूमि कम्पार्टमेंट क्र. पी-261 के अन्तर्गत प्राकृतिक नाला को डायवर्सन करने की अनुमति वायत्।**सन्दर्भ:-** आपका पत्र क्र. NCL/KHD/GM/Min/Env/FC 53.142/2024-25/4246 दिनांक 20.04.2024

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा नाला डायवर्सन की अनुमति प्रकरण प्रस्ताव निम्नानुसार है:-

1. कोल माइन्स हेतु प्रस्तावित वनभूमि 1697.906 हे. कम्पार्टमेंट क्र. पी-261 खड़िया रेंज के अन्तर्गत तीन मौसमी प्राकृति नाले में प्रभावित हो रहे हैं।
2. नाला क्र. 1 :- नाले की लम्बाई 380 मी. है। नाले का बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
3. नाला क्र. 2:- नाले की लम्बाई 840 मी., बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
4. नाला क्र. 3:- नाले की लम्बाई 1245 मी., बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। नाले का उद्गम एवं अंत खदान के अन्दर होने के कारण नाला का हिस्सा दर हिस्सा कटता जाएगा अतः डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
5. बलिया नाला क्र. 4:- नाले का बहाव उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। नाले का उद्गम एवं अंत खदान की बाउण्ड्री लाइन के बाहर होने के कारण डायवर्सन की आवश्यकता नहीं है।
6. प्रकरण के साथ GRID Plan, Cross Section संलग्न है।

सीजनल ड्रेन डायवर्सन स्थल खदान के अन्दर प्रस्तावित किया गया है, जिसे कार्ययोजना अनुसार 3-4 वर्ष के बाद खदान में कार्य प्रारंभ होने के पूर्व निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। अतः निम्न शर्तों के साथ सीजनल ड्रेन डायवर्सन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-

1. प्रस्तावित सीजनल ड्रेन में प्रवाहित जल को प्रदूषण से बचाने की व्यवस्था की जावे ताकि जल का उपयोग सिंचाई, निस्तार व अन्य प्रयोजन में किया जा सकें।
2. वर्षाकाल में उक्त सीजनल ड्रेन में प्राकृति नालों से जल संग्रहीत किए जाने की व्यवस्था की जाना आवश्यक है ताकि नाले का प्राकृतिक श्रोत बना रहे और जल का स्थानीय तौर पर समुचित उपयोग होता रहे।
3. सीजनल ड्रेन निर्माण प्रारंभ होने तथा कार्य पूर्ण होने की सूचना के साथ ही निर्माण कार्य जल संसाधन विभाग के मापदंडों पर कराया जावे।
4. नाले से औद्योगिक प्रयोजन हेतु पानी की आवश्यकता होने पर नियमानुसार प्रपत्र-199 में मांग पत्र प्रस्तुत कर आवंटन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

सहपत्र:- शून्य।(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्रीजल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरीली
जिला-सिंगरीली (म0प्र0)सिंगरीली दिनांक **27/4/2024**पत्र क्र0 **622** तकनीकी / 2024**प्रतिलिपि:-**

मुख्य अभियन्ता गंगा कछार जल संसाधन विभाग रीवा की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

सहपत्र:- शून्य।(एस.एम.तिवारी)
कार्यपालन यंत्रीजल संसाधन संभाग क्र. 2 सिंगरीली
जिला-सिंगरीली (म0प्र0)

नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातन कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुबंधी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)



महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & ISO: 45001 Certified Company

पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.)पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220

Phone : 05446-276279 (O), 267280 (R) Fax : 05446-276274, 07805-25610 e-mail : rgmbin.ncl@coalindia.in Website : www.ncl.in

No.: Bina/Forest/MP Forest/23/127

Dated: 21.06.2023

To

Nodal Officer (FC/LM)

(Principal Chief Conservator of Forests)

Govt. of Madhya Pradesh, Satpura Bhawan,

Bhopal-462004

Subject: - Application for transfer of diverted 7.623 Ha Forest Area from Bina Opencast Project of M/s Northern Coalfields Limited to Khadia Opencast Project of Northern Coalfields Limited.

Ref: - FC Stage- II issued by MoEF, New Delhi (FC Division) vide F.No. 8-58/2005-FC dated 13th August 2007.

Dear Sir,

With reference to above subject matter and letter under reference (copy enclosed as **Annexure I**), this is to submit that 378.935 Ha land has been diverted in favor of M/s Northern Coalfields Limited for mining of coal in Bina Opencast Project. Out of the above 378.935 Ha Forest Land, 7.623 Ha Forest Land is required to be transferred to the adjoining Khadia Opencast Project of the same company i.e., Northern Coalfields Limited.

As per the approved Mining Plan of the proposed EC expansion from coal production of 10.5 MTPA to 17.5 MTPA, land use plan of Bina Expansion OCP excludes above 7.623 Ha Forest Land to merge the same with the adjoining Khadia Opencast Project.

In view of the above, it is requested to kindly transfer the 7.623 Ha Forest Land from Bina Opencast Project to the adjoining Khadia Opencast Project of the same company i.e., Northern Coalfields Limited. Khadia Opencast Project has submitted an undertaking for transfer and compliance of conditions of FC of above 7.623 ha Forest Land, a copy of which is enclosed as **Annexure II**.

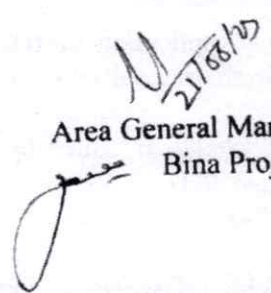
Further, it may be kindly noted that process of NPV and CA has already been completed for the entire 378.935 Ha Forest Land by Bina OCP, a copy of supporting documents is enclosed herewith as **Annexure III**.

After excluding 7.623 Ha Forest Land from Bina OCP, revised land use plan of Bina OCP may be considered as per the approved Mining Plan of the proposed EC expansion from 10.5 MTPA to 17.5 MTPA vide MoEF&CC's proposal no. IA/UP/CMIN/428886/2023 dated 12/05/2023 (copy of EDS enclosed as **Annexure IV**).

In view of the above, it is requested to kindly consider the proposal for transfer of diverted 7.623 Ha Forest Land from Bina Opencast Project of M/s Northern Coalfields Limited to Khadia Opencast Project of Northern Coalfields Limited as well as change in land use plan of Bina Opencast Project.

Enclosures: As above

Yours faithfully


Area General Manager
Bina Project

Copy for kind information to:

1. Chief Conservator of Forests, Rewa
2. Director Tech. (P&P), NCL, Singrauli
3. District Forest Officer, Singrauli
4. Area General Manager, Khadia Area, NCL, Singrauli
5. General Manager (Env. & Forest), NCL, Singrauli

ANNEXURE-I

F. No. 8 - 58/2005-FC
Government of India
Ministry of Environment & Forests
(FC Division)

3246
27-8-07

Parvatan Bhawan
CGO Complex, Lodhi Road
New Delhi-110 003

Dated: 13th August, 2007

To
The Principal Secretary (Forests),
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal.

Sub: Diversion of 378.935 ha. of forest land for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh

Sir,

I am directed to refer to your letter No. F-1 / 368 / 05 / 10-11 / 1345 dated 31.05.2005 on the above mentioned subject, wherein the above proposal for diversion of 378.935 ha. of forest land for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh was submitted seeking prior approval of the Central Government in accordance with Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980.

2. After careful consideration of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee, the Central Government granted in-principle approval to the said proposal under Section-2 of the Forest (Conservation) Act, 1980, on 18.07.2006. The request of the User Agency, that the Condition No 1 of the order dated 18.07.2006 may be changed suitably incorporating therein raising Compensatory Afforestation over double degraded forest land as is applicable to Central Government Public Undertaking, was placed before the Forest Advisory Committee in its meeting held on 27.09.2006. The Forest Advisory Committee recommended to change the Condition No. 1 of the order dated 18.07.2006 as follows:- "The Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over the degraded forest land double in extent to the area broken after 1980, at the cost of the User Agency."

3. A compliance report has been received from the Nodal Officer (FC), Madhya Pradesh, vide letter No. F-1/368/05/10-11/460 dated 21.02.2007. After considering the proposal and compliance of the stipulated conditions by the State Government, the Central Government hereby grants approval, under the Forest (Conservation) Act, 1980, for diversion of 378.935 ha. of forest land for Bina Extension Open-Cast Mining project for coal in favour of M/S. Northern Coal Fields Limited in District Sidhi, Madhya Pradesh, subject to fulfilment of following conditions :-

1. Legal status of the forest land shall remain unchanged.
2. The Compensatory Afforestation shall be raised and maintained over degraded forest land double in extent to the area broken after 1980, by the User Agency at the Project Cost.

3. The State Government shall charge the Net Present Value of the forest area diverted under this proposal from the User Agency as per the orders of the Hon'ble Supreme Court of India dated 30.10.2002 and 01.08.2003 in IA No. 566 in WP (C) No. 202/1995 and as per the guidelines issued by this Ministry vide letters No. 5-1/1998-FC (Pt. II) dated 18.09.2003, as well as letter No. 5-2/2006-FC dated 03.10.2006 in this regard.
4. The State Government shall deposit NPV and all other funds with the Ad-hoc Body of Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA) in Account No. CA 1579 of Corporation Bank, Block-II, Ground Floor, CGO Complex, Phase-I, Lodhi Road, New Delhi-110003.
5. Additional amount of NPV of the diverted forest land, if any, becoming due after finalization of the same by the Hon'ble Supreme Court of India on receipt of the report from the Expert Committee, shall be charged by the State Government from the User Agency.
6. The User Agency shall create, fence and maintain a proper safety zone around the mining area. The User Agency shall deposit funds with the Forest Department for the creation, protection and regeneration of the safety zone area, and also shall bear the cost of afforestation over one and a half time of the safety zone area in degraded forest elsewhere.
7. Phased reclamation of the mine shall be carried out by the User Agency as per the approved Reclamation Plan at the Project Cost.
8. Rehabilitation and resettlement of the displaced persons shall be carried out by the User Agency as per the R & R plan submitted for the purpose.
9. Demarcation of the area shall be done on ground at the project cost using four feet high RCC pillars with serial numbers, forward and back bearings and distances from pillar to pillar.
10. Trees shall be felled only when it becomes necessary and that should be done under strict supervision of the State Forest Department.
11. No labor camps shall be established on the forest land.
12. Sufficient firewood shall be provided by the User Agency to the laborers at the project cost after purchase from the State Forest Department/Forest Development Corporation.
13. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the proposal.
14. The User Agency shall ensure that there should be no damage to the wildlife in the area.
15. All other standard conditions stipulated for Mining Projects shall be complied with by the User Agency.

Yours faithfully,

(A.K. Joshi)

Assistant Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Principal Chief Conservator of Forests, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
2. The Nodal Officer, Office of the PCCF, Government of Madhya Pradesh, Bhopal
3. The Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Lucknow
4. User Agency
5. RO (HQ), New Delhi/ Monitoring Cell / FC Div.
6. Guard file.

(A.K. Joshi)

Assistant Inspector General of Forests

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड
खड़िया परियोजना
(विश्वरूप कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुबंधी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
Khadia Project
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

Office of General Manager



CIN: U11102MP1985CL01003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

थाना-शक्तिनगर, जिला-सोनभद्र (उ.प्र.) पिन-231222/ Thana-Shaktinagar, Dist. Sonebhadra (U.P.) Pin- 231222
Phone: 05446- 232274, (FAX) 05446- 232274 Email: cgm.khd@gmail.com, website www.ncil.in


KHD/GM/M/Env/Transfer of 7.623 Ha/2023-24/3913

Date: 21/06/2023

Undertaking for Compliance of Stage-I/II conditions

Undertaking is hereby submitted for the transfer of 7.623 Ha Forest Land from to Bina Extension Opencast Mining Project to Khadia Expansion Opencast Project, NCL:

- Expansion of Khadia Opencast Project (from 14 MTPA to 20 MTPA) was approved in NCL board and further Terms of Reference (ToR) was granted by MoEF&CC vide J-11015/255/2006-IA.II (M) dated 14.02.2022.
- The complete leasehold area on which ToR of Khadia Project has been granted (1697.906 Ha), includes 7.623 Ha Forest Land of 378.935 Ha Forest Land earlier diverted to Bina Extension Opencast Mining Project. Specific condition no. 4(ii) of ToR issued to Khadia OCP for 20 MTPA states that "PP to seek amendment in Bina Extn prior to file EC application for Khadia Expansion for the area falling within the Khadia Mine and also seek transfer of FC for respective area"
- It is certified that all the conditions stated in the Stage -I and Stage- II letters of diversion of the 378.935 forest land of Bina Extension Opencast Mining Project (containing 7.623 Ha) will be complied.


21/06/2023
Area General Manager
Khadia Area, NCL



क्रमांक/एन-1/368/03/10-11/

भीमाल विनांक

प्रेषक,

डी० अग्निवेश शुक्ला,

(भा० न० ०१०)

मुख्य वन संरक्षक (मू.-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण अधिनियम 1980, मध्यप्रदेश।

प्रति,

सहायक वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
पर्यावरण भवन सी०जी०ओ० काम्पलेक्स
लोधी रोड नई दिल्ली 110003।

विषय:- नार्दन कोल फील्ड्स लिमिटेड की घाटी विस्तार परियोजना हेतु 378.935 हेक्टेयर
वनभूमि का प्रत्यावर्तन बायत्।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्र क्रमांक/8-58/2005 एफ.सी. दिनांक 18.07.06 एवं समसंख्यक
पत्र दिनांक 29.07.06.

महोदय,

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार से उक्त संदर्भित पत्रों से प्राप्त प्रथम चरण स्वीकृति
का पालन प्रतिवेदन निम्नानुसार प्राप्त हुआ है -

1. शर्त क्रमांक-1 के पालन में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु आवेदित वन भूमि के बदले में दुगने बिगड़े
वनक्षेत्र पर रोपण हेतु योजना अनुसार रुपये 5,23,02,000/- की राशि आवेदक संस्थान से जमा कराई
जा चुकी है।
2. शर्त क्रमांक-4 के पालन में आवेदित वनभूमि का वर्तमान शुद्ध मूल्य (NPV) की राशि रुपये 6
लाख प्रति हेक्टेयर की दर से रुपये 22,73,61,000/- आवेदक संस्थान से प्राप्त की जाकर वन विभाग
के खाते में जमा कराई जा चुकी है, तथा एन.पी.वी. की दर के पुनरीक्षण की स्थिति में यदि अतिरिक्त
राशि निश्चित होती है तो उसे जमा करने हेतु आवेदक संस्थान द्वारा बचन/प्रमाण पत्र दिया गया है।

P.O. *[Signature]*
[Signature]
2/1/2

62
24/2/07

शर्त क्रमांक-6 के पालन में सेप्टीजोन निर्माण हेतु रुपये 6,90,000/- की राशि आवेदन संस्थान से प्राप्त की गई है।

उपरोक्त समस्त प्राप्त राशि वन मंडलाधिकारी पूर्व सीधी के पी०डी० खाता क्रमांक ई.एस./2 में दिनांक 4.12.06 से जमा कराई जा चुकी है।

4. अन्य अधिरोपित सगरत शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान द्वारा बचन/प्रमाण-पत्र प्रेषित किये गये हैं।

उपरोक्तानुसार प्रथम चरण स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की पूर्ति हो जाती है, प्राप्त पालन प्रतिवेदन गव्य अभिलेख के संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की अंतिम औपचारिक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

~~सहोदर~~

(डी० अनिमेष शुक्ला)

भोपाल दिनांक 21/2/07

पू०/क्रमांक/एफ-1/368/05/10-11/ 46)

भोपाल।

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय ई-5 रविशंकर नगर भोपाल की ओर पालन प्रतिवेदन की प्रति सहित।
2. वन संरक्षक सीमा वृत्त सीमा मध्यप्रदेश।
3. जिलाध्यक्ष (खनिज शाखा) सीधी मध्यप्रदेश।
4. वन मंडलाधिकारीपूर्व सीधी वन मंडल सीधी गओ।
5. मुख्य महा प्रबंधक एन.सी.एल. बीना विस्तार परियोजना पोस्ट बीना जिला सोनभद्र (गओ)।
6. आधिदासी कार्यपालक एस.ई.सी.एल. काल परेसर रायसेन रोड़ पिपलानी भोपाल।

की ओर सूचनार्थ अर्पित।

संलग्न:- (अनु क्र. 1 हेतु)

मुख्य वन संरक्षक(नू-प्रबंध)

गओ भोपाल

FOR: DT (PEP), NCL

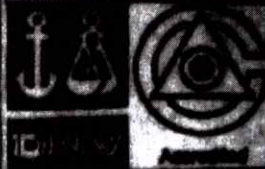
APT: CGM, NCL, BINA PROJ.

FROM: PE, SECL BHOPAL.

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड

बीना एक्सटेंशन परियोजना

पञ्जाब - बीना प्रोजेक्ट, बिना बीनवा - 231 220 (उ.प्र.)



AN ISO 14001
Company

Northern Coalfields Limited

Office of the Chief General Manager

PO : Bina Project, Dist : SONBHADRA 231 220 (U.P.)

Tel : 05445-278278, 07905-388016 Fax : 05445-278274, 07905-388108

Registered Firm
DNV Certification S.V.
The Netherlands

पत्रांक सं. बी/बीए/बीना विस्तार/बनभूमि नमो/06/413

दिनांक : 28.11.2006.

प्रति

बीना विस्तार वन मण्डल अधिकारी,

पूर्व सीधी वन मण्डल,

सीधी (उ.प्र.)

विषय: नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड की बीना विस्तार परियोजना

हेतु 378.935 हेक्टेयर बनभूमि के प्रत्यावर्तन बाबत।

संदर्भ : (I) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार का

पत्र क्रमांक F.No. 8-58-2005/FC दिनांक 18.7.2006.

एवं F.No. 8-58-2005/FC दिनांक 29.07.2006.

(II) आपका पत्र क्रमांक/नामो/2154 दिनांक 22/8/2006.

महोदय,

कृपया उपरोक्त पत्रों का संदर्भ लेते का कष्ट करें। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एन.सी.एल. बीना विस्तार परियोजना हेतु 378.935 हे० वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति में अतिरिचित शर्तों के अनुपालन आख्या निम्नलिखित है -

1. वैकल्पिक दूधारीयन योजना के अन्तर्गत वांछित धन राशि रु. 5,23,02,000/- (पाँच करोड़ तेईस लाख दो हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट संख्या /86570 दिनांक 28.11.06 वन मण्डल अधिकारी पूर्व सीधी के नाम स्टेट बैंक आफ इण्डिया की सीधी शाखा में देय इस पत्र के साथ प्रेषित है।
2. शर्त क्रमांक (II) एवं (III) भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के पत्रांक 8-58/2005-FC दिनांक 29.07/2006 द्वारा निरस्त / (Delete) कर दी गई।



शर्त क्रमांक (A) राज्य प्रदेश शासन द्वारा नैट प्रेजेंट लेण्ड (N.P.U) की वर्गीकृत राशि रुपये 22,73,61,000.00 लाख (रुपये बाईस करोड़ सत्तर लाख रुपये मात्र) बैंक ड्राफ्ट नं. /A.G.F./... दिनांक 28.11.06. इस पत्र के साथ प्रेषित है ।

शर्त क्रमांक (U) - वचन पत्र संलग्न है ।

5. शर्त क्रमांक (UI) - राज्य प्रदेश शासन द्वारा वर्गीकृत धन राशि रुपये 6,90,000 लाख (बैंक ड्राफ्ट नं. /A.G.F./... दिनांक 28.11.06 संलग्नित है ।

6. शर्त क्रमांक (UII) - न.प्र. शासन द्वारा अनुपातन किया जाता है ।

7. शर्त क्रमांक (UIII) - वचन पत्र संलग्न है ।

आपसे अनुरोध है कि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा संदर्भित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु सहायित्व स्वीकृति देते समय अतिरिक्त शर्तों की अनुपालन आवश्यकता शीघ्रतम शीघ्रतम मुख्य वन संरक्षक (मू प्रबन्धन / Land Management) राज्य प्रदेश शासन की प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि भारत सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके ।

धन्यवाद,

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार

प्रति -

01. मुख्य वन संरक्षक (मू प्रबन्धन), न.प्र. शासन, भोपाल ।
02. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय) के. कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, इंदौर, भोपाल ।
03. वन संरक्षक, रीय वृत्त, रीवा ।
04. सहायक वन मन्त्री निरीक्षक (AFC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली ।

से -

01. निदेशक (तक - योजना एवं परियोजना) / एन.सी.एल., सिंगरीली - सादर सूचनाार्थ
02. मुख्य महाप्रबन्धक (T.S.) / एन.सी.एल., सिंगरीली
03. मुख्य महाप्रबन्धक (C.P.) / एन.सी.एल., सिंगरीली
04. मुख्य वन संरक्षक / एन.सी.एल., सिंगरीली
05. श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, अधिवासी कार्यपालक, भोपाल
- परियोजना अधिकारी, बीना विस्तार

Dr. Y. J. Singh
मुख्य महाप्रबन्धक,
बीना परियोजना
N.C.E.L., Singareeni
Bina Extension

PARTICULARS
(1)

AMOUNT

(2)

Colno**No's (with details)****Cheque (with details)**

Total Rs.

280353,00/200

[Sharma P. P. Sidhi]

Annexure IV

No. S/N Description

1 The proposal is for increase in production capacity from 10.5 to 17.5 MTPA along with increase in mine lease area upto 2079.221 ha which also involves the transfer of 7.623 ha of forest area from existing mine to adjacent Khadia mine. Therefore, the mine lease area of existing (old) extension project is being reduced and further increasing for expansion. Therefore, as per extant rule of EIA Notification 2006 altering the mine area based on which EC was granted, attracts modification of EC dated 28.07.2022. PP is, therefore, advised to take first amendment of EC and later proposal of expansion of the same mine shall be considered on merits. The proposal is therefore not applicable for expansion.

2 Other
(Option
a)

राजस्व आदेश अनुवृत्ति-पत्र
मामला क्रमांक अ/20(3) वर्ष 2024-25

(2)

(3)

12/08/2024

प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी हटा से प्राप्त। अवलोकन किया।

महाप्रबंधक, खडिया परियोजना पोस्ट शक्तिनगर, जिला सोनभद्र, उ.प्र. वर्तमान, सिंगरोली म.प्र. ने मौजा घुघरी प.ह.नं. 54 बमनी, तहसील पटेरा में स्थित भूमि ख.नं. 73 रकबा 92.230 हेक्ट. में से रकबा 53.142 हेक्ट. वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक 0811280704054-APP-20781418 प्रेषित कर मूल दस्तावेज संलग्न किये जाने के उपरांत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुविभागीय अधिकारी हटा को प्रतिवेदन हेतु भेजा गया।

अनुविभागीय अधिकारी हटा ने नायब तहसीलदार कुम्हारी तहसील पटेरा से जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण प्रस्तुत किया है। नायब तहसीलदार कुम्हारी ने अपने जांच प्रतिवेदन में लेख किया है, कि रा.नि. एवं हल्का पटवारी से संयुक्त जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन प्राप्त किया गया, जिसमें ग्राम घुघरी प.ह.नं. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 73 रकबा 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. भूमि नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड एन.सी.एल. सिंगरोली गैर वन भूमि वनोपरण (सी.ए.) को हस्तांतरित किये जाने हेतु उपयुक्त पाई गई है। ग्राम में इश्तहार का प्रकाशन कराया गया, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त की गई। रा.नि. एवं हल्का पटवारी द्वारा ग्राम का कुल भौगोलिक रकबा 382.96 हेक्ट. ग्राम के गैर खाते का रकबा 281.24 हेक्ट. ग्राम के खाते का रकबा 101.72 हेक्ट. ग्राम में खाते के कुल रकबा के मान से 2 प्रतिशत चरनोई का रकबा 2.02 हेक्ट., ग्राम में उपलब्ध चरनोई का कुल रकबा 59.92 हेक्ट. है, जो 2 प्रतिशत के मान से 57.90 हेक्ट. अधिक है। ख. नं. 73 रकबा 92.23 हेक्ट. मद पहाड़ चट्टान में दर्ज है। अतः ग्राम घुघरी ग्राम पंचायत बमनी प.ह.नं. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. नार्दन कोलफील्डस लिमिटेड एन.सी.एल. सिंगरोली भूमि मद पहाड़ चट्टान में से म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(2) के तहत नोईयत परिवर्तन कर म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अनुसार प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी हटा के माध्यम से प्रस्तुत किया है।

अनुविभागीय अधिकारी हटा ने तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमत होते हुये ग्राम घुघरी ग्राम पंचायत बमनी प.ह.नं. 54 में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 92.23 हेक्ट. में से 53.142 हेक्ट. वनविभाग म.प्र.शासन के हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण किया। कम्प्यूटर अभिलेख खसरा वर्ष 2024-25 में ग्राम घुघरी तहसील पटेरा जिला दमोह में स्थित ख.नं. 73 रकबा 92.2300 हेक्ट. पहाड़ म.प्र. राज्य सरकार चट्टान दर्ज है। ग्राम पंचायत बमनी जनपद पंचायत पटेरा जिला दमोह ने पत्र क्रमांक/गा.पंचा/2024 दिनांक 04.04.2024 से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। वनमंडल अधिकारी, वनमण्डल (सा) दमोह ने पत्र क्रमांक/मा.चि./2269 दमोह दिनांक 01.05.2024 से लेख किया है, कि ग्राम घुघरी में स्थित ख.नं. 73 रकबा 92.93 हेक्ट. में से रकबा 82.62 हेक्ट. वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। प्रकरण को जिला नजूल निर्वर्तन समिति दमोह में प्रस्तुत किया गया। जिसके प्रस्ताव क्र. 09 बैठक दिनांक 11.06.2024 से प्रकरण को अनुमोदित किया गया है।

अतः प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों, तहसीलदार पटेरा के जांच प्रतिवेदन एवं अनुविभागीय अधिकारी हटा की अनुशंसा तथा जिला नजूल भूमि निर्वर्तन समिति दमोह से प्राप्त अनुमोदन के आधार पर शासन की विभिन्न परियोजनाओं में प्रभावित होने वाली वन भूमि के बदले मौजा घुघरी प.ह.नं. 54 तहसील पटेरा में स्थित शासकीय भूमि ख.नं. 73 रकबा 92.230 हेक्ट. में से रकबा 53.142 हेक्ट. मद पहाड़ को वन विभाग (म.प्र.शासन) को म.प्र. नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के अध्याय-02 की कंडिका-18 के तहत निम्नानुसार हस्तांतरित की जाती है।

प्रकरण आदेशानुसार कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी हटा भेजा जाता है।

कलेक्टर

जिला-दमोह

12/6/24

79°45'0"E

79°45'15"E

Annexure - H



Plot No 73

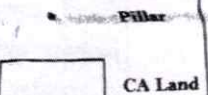
List of Geographical Co-ordinates (in WGS 84) of Pillars Along CA Land Ghugri Mouza

Name	WGS84 Latitude	WGS84 Longitude
G1	23° 52' 58.809" N	79° 44' 54.503" E
G2	23° 53' 2.237" N	79° 45' 0.654" E
G3	23° 53' 5.508" N	79° 45' 6.831" E
G4	23° 53' 8.610" N	79° 45' 12.656" E
G5	23° 53' 11.310" N	79° 45' 17.628" E
G6	23° 53' 6.236" N	79° 45' 21.459" E
G7	23° 52' 59.907" N	79° 45' 21.868" E
G8	23° 52' 54.421" N	79° 45' 25.476" E
G9	23° 52' 49.667" N	79° 45' 23.190" E
G10	23° 52' 44.778" N	79° 45' 20.995" E
G11	23° 52' 42.012" N	79° 45' 18.205" E
G12	23° 52' 39.081" N	79° 45' 15.279" E
G13	23° 52' 37.556" N	79° 45' 9.497" E
G14	23° 52' 38.513" N	79° 45' 4.843" E
G15	23° 52' 44.412" N	79° 45' 4.853" E
G16	23° 52' 51.094" N	79° 45' 4.874" E
G17	23° 52' 50.988" N	79° 44' 54.657" E

Plot Wise Area of CA Land (Ghugri Mouza)

Plot No	Area (in Ha)
73	53.142
Total Net Area	53.142 Ha.

Legend



Copyright in this drawing is vested in CMPDL
Unauthorized copying or use is not permitted.

Customer

Northern Coalfield Limited

Project

Preparation of Georeferenced Boundary Map of CA Land
(53.142 Ha) against Forest Land (53.142 Ha.) at Khadia Project, NCL

Job No.

Subject

Plan Showing CA Land at
Village- Ghugri
Tehsil: Patara
District: Damoh

Activity

Name

Designation

Signature

Date

Surveyed /
Processed
by

S Dutta

Sr. Surveyor(C)

Checked
by

S.K.Dixit

GM (Mining)

Approved
by

Atal Bihari

RD RI- VI

Scale - 1:4,000

Sheet No. 1 of 1

Drg No.

HQS&D24107

REV. 0



79°45'0"E

79°45'15"E

79°45'30"E

23°53'0"N

23°52'45"N

23°52'30"N

महाप्रबन्धक
खडिया परियोजना